दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>निर्णय पारित: 18 जनवरी, 2024</u>

रि.या.(सि.) 8398/2021, सि.वि.आ. 25969/2021

एस.एस. दास ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री संजय घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अनुराग ओझा और श्री करण अग्रवाल अधिवक्तागण

बनाम

भारत संघ ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, भारत संघ के लिए के.सर.स्था.अधि.

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. कामेश्वर राव
माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार मेंदिरत्ता

निर्णय

<u>न्या. वी. कामेश्वर राव</u>

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली (संक्षेप में, "अधिकरण") द्वारा मूल आवेदन सं. 2640/2019 (संक्षेप में, "मू.आ.") में 2 जुलाई, 2021 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर

की गई है, जिसके तहत अधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर मू.आ. को पैराग्राफ 12 में, निम्नानुसार बताते हुए खारिज कर दिया है:-

> *"12. पुनरीक्षण समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन का सार पहले के पैराग्राफ में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रत्यर्थीगण ने जवाबी शपथ पत्र में इसी का विस्तार से उल्लेख किया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न हलकों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि आवेदक ने प्रतिपाटन के लिए संदर्भित पद पर रहते हुए कई अनुग्रह करने की मांग की थी। यह सच हो सकता है कि ऐसी मांगों के बारे में कोई सबूत नहीं है। हालाँकि, अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में इसकी आवश्यकता होगी। एफ.आर. 56(ज) के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे आरोपों पर ध्यान दे सकता है। एक बार जब कर्मचारी को उनके सेवानिवृत्ति लाभ पूरी तरह से प्रदान कर दिए जाते हैं, और सामान्य प्रक्रिया की तुलना में थोड़ा पहले सेवानिवृत्त हो जाता है, तो दंडात्मक कार्रवाई के लिए संदर्भित प्रयोग आवश्यक नहीं है।*
>
> *13. **अशोक कुमार अग्रवाल** बनाम भारत संघ और अन्य (मू.आ. सं. 1835/2020), में अधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-*
>
> > *"38. हो सकता है कि जुर्माना लगाने की स्थिति न रही हो। हालांकि, इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसलों का सार यह है कि कर्मचारी के समग्र रिकॉर्ड को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जा सकता है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए, यह नियुक्ति प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि है, जो बदले में अन्य प्रशासनिक निर्णयों की तुलना में न्यायिक पुनरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है।*
> >
> > *39. भारत के संविधान के अनुच्छेद XXIV के तहत प्रावधानों की बारीकी से जांच करने पर, जिसमें अनुच्छेद 308 से 314 या सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियम या मौलिक नियम शामिल हैं, से पता चलता है कि भले ही सिविल सेवकों को कई तरह की सुरक्षा दी गई हो, लेकिन प्रशासन को कर्मचारियों को दंडित करने या उनको सेवाओं*

से विमुक्त करने की शक्ति दी गई है, जो कदाचार के कृत्यों के सबूत या यह दिखाने के लिए सामग्री की मौजूदगी पर निर्भर करता है कि कर्मचारी को सेवा में बनाए रखना संभव नहीं है। कदाचार के आरोपों की जांच करते समय, वह मानक है जिसे अनुच्छेद 311 (2) (ख) और संबंधित सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमों के दूसरे परंतुक द्वारा शामिल किए गए हैं, असाधारण मामलों में समाप्त किये जा सकते हैं।

40. (सी.सी.ए.) नियमवाली के नियम 14 के तहत जांच के बाद या अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों को लागू करने के बाद सेवा से बर्खास्तगी के कारण सिविल सेवकों को हुई कठिनाई, यदि बहुत बड़ी नहीं है, तो असाधारण है। पेंशन, जो लगभग संपदा के रूप में है, वापस ले ली जाती है। अन्य लाभ, जो कर्मचारी द्वारा अपने जीवन के अधिकांश समय में की गई सेवा के लिए पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं। इसके विपरीत, एफ.आर. 56(ज) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रभाव केवल सेवानिवृत्ति की आयु को आगे बढ़ाना होगा और इससे अधिक कुछ नहीं। राज्य महसूस करता है कि यह उसके लिए सुरक्षित होगा, यदि कर्मचारी अपनी सेवा के शेष भाग के लिए अपने कार्य पर नहीं है। मोटे तौर पर कहा गया है कि बर्खास्तगी और निष्कासन जैसे प्रमुख दंड लगभग घातक हथियार हैं, जबकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति सिर्फ एक शांतिदायक दवा है। जाहिर है कि इसी कारण से माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप को न्यूनतम कर दिया था। अपवाद वे होते हैं जहां आदेश दुर्भावना से भरा हुआ है या ऐसे अभिवाक को उचित ठहराने के लिए कोई सामग्री मौजूद नहीं है। हालांकि, इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं है।"

14. इस मामले में भी लगभग यही स्थिति है। पुनरीक्षण में भी, आवेदक द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखा गया और समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश का भी उल्लेख किया गया।

15. हम मूल आवेदन में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।"

2. अभिलेख से नोट किए गए तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता वर्ष 1989 में भारतीय व्यापार सेवा (संक्षेप में "आई.टी.एस.") में शामिल हुआ। 1994 में उन्हें विदेश व्यापार उप-महानिदेशक (संक्षेप में "डी.जी.एफ. टी.") के पद पर पदोन्नत किया गया और वर्ष 2001 में उन्हें संयुक्त डी.जी.एफ.टी. के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें वर्ष 2006 में अकृत्यक चयन श्रेणी (संक्षेप में "एन.एफ.एस.जी.".) के आधार पर भी पदोन्नत किया गया था और वर्ष 2008 में केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए चुना गया था।

3. यह कहा गया है कि एक अन्य अकृत्यक उन्नयन (संक्षेप में, "एन.एफ.यू.") उन्हें वर्ष 2011 में दिया गया था और वे वर्ष 2014 में प्रतिपाटन महानिदेशालय (संक्षेप में, डी.जी.ए.डी.) में निदेशक बने। उन्हें वर्ष 2017 में क्षेत्रीय संयुक्त डी.जी.एफ.टी., के रूप में गुवाहाटी और शिलांग में तैनात किया गया था। इसके बाद, उन्हें 16 नवंबर, 2017 को संयुक्त सचिव के स्तर पर आई.टी.एस. के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (संक्षेप में "एस.ए.जी.") में रखा गया और 27 फरवरी, 2018 को नियमित आधार पर उन्हें एस.ए.जी. में पदोन्नत किया गया।

4. यह भी कहा गया है कि 10 मई, 2018 को याचिकाकर्ता के नियुक्ति प्राधिकारी ने मौलिक नियमों (संक्षेप में "नियम") के एफ.आर. 56(ञ) के तहत

शक्ति का उपयोग करके, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले ही, उन्हें सेवा से सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित किया। उसके अनुसार, प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने वाले पारित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका को प्रत्यर्थी द्वारा 13 जून, 2019 को खारिज कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा 10 मई, 2018 के समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश और 13 जून, 2019 के पुनर्विचार की अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देते हुए मू.आ. दायर किया गया।

5. अधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसका सेवा का रिकॉर्ड बेदाग है और उन्होंने समय पर कई पदोन्नति अर्जित की है और इस तरह, किसी भी समय, उन्हें किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ा और उनके ए.सी.आर. को भी लगातार उच्च दर्जा दिया गया।

6. उनका यह भी कहना था कि प्रत्यर्थी के पास उनके विरुद्ध एफ.आर. 56(ञ) नियमों के तहत शक्ति का उपयोग करने का कोई औचित्य या आधार नहीं था। उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह करते हुए समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया गया था और ऐसा कदम केवल केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही उठाया जा सकता था और इस मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया।

7. जबकि, अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी का मामला यह था कि प्रतिपाटन विभाग के प्रशासन की सफाई करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, 50 वर्ष की आयु पार कर चुके विभिन्न अधिकारियों के मामलों की पुनरीक्षण करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने विभिन्न अधिकारियों के प्रासंगिक सेवा के अभिलेखों की जांच की और याचिकाकर्ता के मामले को समयपूर्व सेवानिवृत्ति देने की सिफारिश की।

8. प्रत्यर्थी का यह भी मामला था कि याचिकाकर्ता की ए.सी.आर. में संबंधित अधिकारियों द्वारा अलग-अलग समय पर कई टिप्पणियां की गईं, जिसमें उसकी ईमानदारी पर संदेह जताया गया और उसके कामकाज के बारे में असंतोष व्यक्त किया गया और चूंकि याचिकाकर्ता विभाग में बहुत वरिष्ठ और संवेदनशील पद पर था, इसलिए निर्धारित मानदंडों का कोई भी छोटा-सा भी विचलन विभाग के कामकाज पर प्रभाव पड़ता है और देश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

9. अधिकरण के समक्ष दोनों पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत मामले तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलोकन करने तथा उनका विश्लेषण करने के पश्चात, इसने याचिकाकर्ता द्वारा दायर मू.आ. को, उसी तरीके से खारिज कर दिया, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 1 में पुनः प्रस्तुत किया गया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अधिकरण द्वारा पारित आदेश को निम्नलिखित तरीके से चुनौती दी है:-

<u>याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

10. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय घोष ने कहा कि 23 जून, 1969 और 10 मई, 1974 के कार्यालय ज्ञापनों ["कार्यालय ज्ञापन"] के अनुसार, मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति (संक्षेप में, "ए.सी.सी.",) की मंजूरी एस.ए.जी. और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए एफ.आर. 56(ञ) के लागु करने के लिए एक पूर्व-शर्त है। उपरोक्त स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वास्तव में, एफ.आर. 56(ञ) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित सभी बाद के कार्यालय ज्ञापनों में एस.ए.जी. के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यह स्थिति समान है। यहां तक कि 21 मार्च, 2014 के कार्यालय ज्ञापन में विशेष रूप से अपने परिशिष्ट और पार्श्व-टिप्पण में उक्त कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख किया गया है। वास्तव में, यह केंद्रीय सेवा समूह ए के संबंध में प्रमुख नियम है।

11. उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आवश्यकता शक्तियों के मनमाने प्रयोग और निर्णय लेने के तरीके के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा है, जिसमें सरकारी कर्मचारी के पक्ष में सुरक्षा उपायों के गुण हैं, और इस तरह का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

12. उनका मामला यह है कि एस.ए.जी. में याचिकाकर्ता की नियुक्ति ए.सी.सी. द्वारा की गई थी और इस प्रकार, उसे हटाने के लिए वही एकमात्र सक्षम प्राधिकारी है। इसका तार्किक परिणाम यह है कि हटाने के प्रभाव वाली

कोई भी कार्रवाई नियुक्ति प्राधिकारी से अलग निकाय द्वारा नहीं की जा सकती है।

13. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कानून यह मानता है कि एफ.आर. 56(ञ) को लागू करने के लिए सिफारिश ए.सी.सी. के समक्ष रखी जानी चाहिए। *"ए.सी.सी. के समक्ष रखने"* की आवश्यकता पूर्ण प्रकटीकरण पर विचार करती है, ताकि इसे एक सुविचारित राय बनाने में सक्षम बनाया जा सके। यह कुछ कार्यों के लिए आवश्यक प्रतिबंधों के समान है। यह लगातार अभिनिर्धारित किया गया है कि मामले को प्रकट नहीं करना या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखना मामले की जड़ तक जाता है और इस विषय पर की गई सभी कार्रवाइयों को निष्प्रभावी कर देता है। [संदर्भ ***स्वर्ण सिंह चंद बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य, (2009) 13 एस.सी.सी. 758***]।

14. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यह एक स्वीकृत मामला है कि प्रत्यर्थी ने मामले को अनुमोदन के लिए या अन्यथा ए.सी.सी. के समक्ष नहीं रखा है। अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के बावजूद, अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और दुर्भाग्य से, अधिकरण ने याचिकाकर्ता की ओर से व्यापक तर्क दिए जाने के बावजूद मामले के इस पहलू को स्वीकार नहीं किया है।

15. उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि एफ.आर. 56(ञ) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई *"सत्यनिष्ठा की कमी"* से संबंधित है, तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए। 10 मई, 1974 के कार्यालय ज्ञापन में विशेष रूप

से केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता है यदि सतर्कता के अभाव में कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया जाता है। उन्होंने ***गुजरात राज्य और अन्य बनाम न्यायमूर्ति आर. ए. मेहता (सेवानिवृत्त) और अन्य, (2013) 3 एस.सी.सी. 1***, के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की सहायता यह तर्क देने के लिए लिया कि अभिव्यक्ति "परामर्श" न्यायिक अवधान के अधीन है और न्यायिक सहमति का अर्थ, निम्नलिखित है:-

> *".....आम तौर पर, परामर्श का अर्थ है किसी विशेष विषय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष विवेचन, जो एक-दूसरे के संबंध में पक्षकारगण के पास मौजूद सभी सामग्री का खुलासा करती है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचती है। हालांकि, ऐसी स्थिति में जहां कानून के तहत एक की राय की प्रधानता है, या तो विशेष रूप से किसी क़ानूनी प्रावधान में निहित है, या निहितार्थ के रूप में, परामर्श का अर्थ सहमति हो सकता है। न्यायालय को किसी दिए गए मामले में तथ्य-स्थिति की जांच करनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या परामर्श की प्रक्रिया, जैसा कि विशेष स्थिति के तहत आवश्यक है, वास्तव में पूरी की गई है....."*

16. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह सुस्थापित विधि है कि, यदि विधि किसी विशेष तरीके से कुछ करने को निर्धारित करता है, तो अन्य सभी तरीके वर्जित हो जाते हैं। [संदर्भ ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह और अन्य, ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 358*** और ***मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य, एम.ए.एन.यू./एस.सी./0209/1977***]।

17. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि, वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग से ऐसा कोई परामर्श नहीं किया गया। वास्तव में, आक्षेपित आदेश से पहले इस मामले की सूचना केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कभी नहीं दी गई है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक संस्था है और प्रत्यर्थी /वाणिज्य मंत्रालय के पदानुक्रम से असंबद्ध एक स्वतंत्र संस्था है। परामर्श का उद्देश्य अनिवार्य रूप से एक स्वतंत्र दृष्टिकोण प्राप्त करना है कि क्या सत्यनिष्ठा का आरोप लगाने वाली सामग्री इस तरह के दृष्टिकोण को बनाने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए मुख्य रूप से किसी विशेष एजेंसी द्वारा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। निर्णय की त्रुटियों वाली विशेष दृष्टिकोण या "प्रश्नगत सत्यनिष्ठा" के बराबर विचलन की समझ एक अस्पष्ट विशेषता होगी यदि इसे "आरोप लगाने वाली निकाय" पर छोड़ दिया जाए। इसलिए आवश्यक सुरक्षा उपाय - सी.वी.सी. के साथ परामर्श का पूर्व आदेश देता है। पुनर्विचार समिति में सी.वी.ओ. (एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी) की उपस्थिति सी.वी.सी. के साथ परामर्श के समान नहीं है। अधिकरण ने इस तथ्य के बावजूद मामले के इस पहलू को नहीं समझा कि मौखिक तर्कों में इस पर व्यापक रूप से विचार किया गया है।

18. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिकरण यह समझने में विफल रहा है कि एफ.आर. 56(ञ) को लागू करने के उद्देश्य से पुनर्विचार, कानूनी रूप से, या तो 50 वर्ष की आयु में या 55 वर्ष की आयु में की जानी चाहिए और इसे उक्त

आयु प्राप्त करने से छह महीने पहले अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता उन अधिकारियों की सूची में एकमात्र ए.सी.सी. नियुक्त व्यक्ति है जिसे बिना किसी प्रतिकूल सामग्री के 55.6 वर्ष की आयु में पुनरीक्षण के लिए चुना गया था। इस प्रकार, ऊपर वर्णित अपनाई गई कार्यवाहियां स्पष्ट रूप से विधि में विद्वेष को इंगित करती हैं, जिसने इस तरह के प्रयोग को बढ़ावा दिया।

19. उनका मामला यह है कि वर्तमान मामले में, एफ.आर. 56(ञ) के लागु करने को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री नहीं है। वास्तव में, संदिग्ध सत्यनिष्ठा से संबंधित टिप्पणी, अभिलेख पर बिना किसी भी सामग्री के है। प्रचुरतापूर्वक से, यह अभियोग कि *'याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा के मामले में अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है, जैसा कि ए.पी.ए.आर. डोजियर से पता चलता है'* तथ्यात्मक रूप से गलत है। सभी ए.पी.ए.आर. के सार से यह पता चलता है कि कभी भी याचिकाकर्ता पर वैसी टिप्पणी नहीं की गई है जैसी टिप्पणी उस पर की गई। इस प्रकार, यदि यह माना जाय कि एफ.आर. 56(ञ) को लागू करने का आधार प्रश्नगत सत्यनिष्ठा है, और यह ए.पी.ए.आर. से लिया गया है, और यदि ए.पी.ए.आर. में ऐसी टिप्पणियाँ नहीं पाए जाते हैं, तो आक्षेपित आदेश "बिना किसी आधार के" न्यायिक स्वीकृति के योग्य है। वास्तव में, कुछ ए.पी.ए.आर. में विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता की ईमानदारी *"ईमानदारी पूरी तरह से निष्कपट है या कुछ भी प्रतिकूल नहीं है"।*

20. उन्होंने प्रस्तुत किया कि ए.सी.सी. के अनुमोदन से याचिकाकर्ता को हाल ही में दी गई पदोन्नति, उसके बाद गैर-मौजूद आधारों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आक्षेपित आदेश 10 मई, 2018 का आदेश विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण बनाता है। यह सुस्थापित विधि है कि एक बार पदोन्नति दिए जाने के बाद किसी नई सामग्री के अभाव में अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जा सकती। [सन्दर्भ ***एम. एस. बिंद्रा बनाम भारत संघ और अन्य, (1998) 7 एस.सी.सी. 310***]।

21. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के हालिया ए.पी.ए.आर. (यहां तक कि अतीत में भी) में भी कोई टिप्पणी नहीं है, जो याचिकाकर्ता की निष्कलंक सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। वास्तव में, नवीनतम ए.पी.ए.आर. (2016-2017) में प्रभावशाली प्रविष्टियाँ दर्ज हैं। यह उनका मामला है कि पूरे सेवा रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए, निरंतरता खोने वाली छिटपुट टिप्पणियों को आरोप लगाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा, सेवा के प्रारंभिक चरण से संबंधित प्रतिकूल प्रविष्टियों के लिए बाहरी और अति-झुकाव से बचा जाना चाहिए जब तक कि यह गंभीर और स्थायी न हो।

22. उनका कहना है कि अधिकरण ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति/एफ.आर. 56(ञ) के उपयोग करने के मामले में न्यायिक पुनरीक्षण से संबंधित बाध्यकारी नजीर को नजरअंदाज किया गया है। कानून स्पष्ट है कि यदि तथ्यों के उसी समूह पर पदोन्नति दी जाती है, जब तक कि एफ.आर. 56(ञ) के उपयोग को उचित

ठहराने वाली नई सामग्री प्राप्त न हो जाय, तो ऐसा उपाय विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिकरण का निष्कर्ष, विशेष रूप से, अनुच्छेद 8 में, विधि के विशुद्ध प्रश्न पर, विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है, जैसा कि ***गुजरात राज्य बनाम उमेदभाई एम. पटेल के मामले में न्यायालय, (2001) 3 एस.सी.सी. 314 में*** उच्चतम न्यायालय द्वारा की टिप्पणियों **को** बाद के निर्णयों ***प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2010) 10 एस.सी.सी. 693*** और ***पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और अन्य बनाम हरि कृष्ण वर्मा (2015) 13 एस.सी.सी. 156*** में लगातार दोहराया गया है।

23. उन्होंने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 9 में अधिकरण के निष्कर्ष विकृत हैं क्योंकि अधिकरण के समक्ष ऐसा कोई उदाहरण नहीं उठाया गया था जो संवेदनशील पदों पर आसीन याचिकाकर्ता की ओर से *'वित्तीय निहितार्थ वाले विचलन'* का संकेत दे सके और इस तरह अधिकरण का अवलोकन प्रत्यर्थी के मामले से परे है।

24. उनका कहना है कि तथ्य यह है कि एक ही अधिकारी अर्थात आलोक वर्धन चतुर्वेदी तीनों समितियों (प्रथम पुनरीक्षण समिति, अभ्यावेदन समिति और द्वितीय पुनरीक्षण समिति) का हिस्सा रहे हैं, इस प्रकार पक्षपात के उचित संदेह ने प्रक्रिया को दूषित कर दिया है। तीन समितियों का हिस्सा बने आलोक वर्धन चतुर्वेदी का विभागीय पक्षपात और दुर्भावनापूर्ण आचरण याचिकाकर्ता के खिलाफ

सद्भावना और द्वेष की कमी का मामला सामने लाता है। [संदर्भ ***आर.पी. कपूर बनाम प्रताप सिंह कैरों, 1965 एस.सी.सी. ऑनलाइन एला. 414***]।

25. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति/एफ.आर. 56(ञ) के लागू करने के मामलों में न्यायिक पुनरीक्षण से संबंधित बाध्यकारी पूर्व निर्णय को नजरअंदाज किया है क्योंकि विधि में स्पष्ट है कि यदि पदोन्नति समान तथ्यों के आधार पर दी गई है, जब तक कि एफ.आर. 56(ञ) को लागु करने को उचित ठहराने वाली नई सामग्री प्राप्त नहीं हो जाती है, तो ऐसा सहारा विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है। **[**संदर्भ ***श्रीमती एस. आर. वेंकटरमण बनाम भारत संघ और अन्य, (1979) 2 एस.सी.सी. 491***]।

26. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने 10 मई, 2018 के आदेश के खिलाफ 1 जून, 2018, 24 जुलाई, 2018, 3 अगस्त, 2018, 30 अगस्त, 2018 को चार अभ्यावेदन दिए हैं, जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इस तरह के अभ्यावेदन का अवसर इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि याचिकाकर्ता 10 मई, 2018 के आदेश के कारणों से अनजान था। आर.टी.आई. जवाबों पर आधारित विभिन्न सामग्रियाँ मनमाने और पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने को प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत की गईं, जिसकी परिणति 10 मई, 2018 के आदेश के रूप में सामने आयी।

27. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अभ्यावेदन समिति की बैठक 07 सितंबर, 2018 को हुई थी, लेकिन उक्त समिति ने अपना विवेक खो दिया,

क्योंकि 30 अगस्त, 2018 का व्यापक अभ्यावेदन जानबूझकर प्रत्यर्थी द्वारा समिति के समक्ष नहीं रखा गया था और केवल 1 जून, 2018 का पहला अभ्यावेदन, जिसे तब पेश किया गया था जब याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आधारों के बारे में जानकारी नहीं थी, पर विचार किया गया। यह स्पष्टतः विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है क्योंकि 30 अगस्त, 2018 के व्यापक अभ्यावेदन, जिसमें सभी आरोपों का खंडन किया गया था, पर विचार करना तो दूर, उस पर गौर भी नहीं किया गया। निष्पक्षता और न्याय, जिसके लिए कानून सरकार को प्रतिबद्ध मानता है, के लिए 30 अगस्त, 2018 के व्यापक अभ्यावेदन के लिए उचित सहमति की आवश्यकता है। प्रत्यर्थी का यह स्वीकार्य मामला है कि इस अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया था।

28. उन्होंने प्रस्तुत किया कि, 30 अगस्त, 2018 के व्यापक अभ्यावेदन पर विचार किए बिना, अभ्यावेदन समिति ने याचिकाकर्ता के मामले को पुनर्विचार के लिए उपयुक्त पाया और मामले को पुनर्विचार के लिए पुनरीक्षण समिति समिति को वापस भेज दिया और अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया।

29. उन्होंने आगे कहा कि दूसरी पुनरीक्षण समिति में भी आलोक वर्धन चतुर्वेदी और अनूप वधावन जैसे वही अधिकारी शामिल थे। उक्त समिति ने, प्रतीत होता है, ऐसी प्रक्रिया अपनायी जो अपने विरचना से ही पक्षपातपूर्ण और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। इस समिति ने उसी अधिकारी को

बुलाया जिसने कथित तौर पर याचिकाकर्ता के खिलाफ 30 मार्च, 2017 को गोपनीय नोट बनाया था। उक्त गोपनीय नोट में बताए गए तथ्य स्पष्ट रूप से असत्य हैं रिकॉर्ड से परे हैं और इसके निर्माता की "व्यक्तिगत रंजिश" के परिणाम हैं। केवल इसी कारण से, बाद के सभी प्राधिकारियों, यानी यू.पी.एस.सी., ए.सी.सी. और विभागीय पदानुक्रम में सतर्कता प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता की बाद की पदोन्नति के समय इसे कोई महत्व नहीं दिया।

30. वास्तव में, 30 अगस्त, 2018 के व्यापक अभ्यावेदन में, याचिकाकर्ता ने वस्तुनिष्ठ तथ्यों से, नोट में स्पष्ट झूठ और अधिकारी के आचरण को प्रदर्शित किया है, क्योंकि उसने अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की है। यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा संबोधित 30 अगस्त, 2018 के अभ्यावेदन को उजागर करने वाले 31 अक्टूबर, 2018 और 02 फरवरी, 2019 के गोपनीय ईमेल को भी नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरी पुनरीक्षण समिति ने विभागीय अभिलेखों से गोपनीय नोट की सच्चाई की सत्यता का निर्धारण करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वस्तुनिष्ठ तथ्यों की जांच करने के बजाय, याचिकाकर्ता की पीठ पीछे इसके निर्माता को बुलाया। यह दृष्टिकोण याचिकाकर्ता के “पीठ पीछे प्रतिकूल साक्ष्य लेने” के समान है।

31. अभ्यावेदन समिति ने दूसरी पुनरीक्षण समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में इस गंभीर चूक को नजरअंदाज किया है और बुद्धिरहित रूप से अपनी

मंजूरी की मुहर लगा दी है। इसके बाद, कागजात सक्षम प्राधिकारी, यानी ए.सी.सी. के समक्ष रखे जाने थे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं।

32. उन्होंने प्रस्तुत किया कि, इस तथ्य को देखते हुए कि पूरे सेवा रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो एफ.आर. 56(ञ) लागू करने की आवश्यकता की पुष्टि करती हो और ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसके प्रति सचेत है, प्रत्यर्थी ने रिकॉर्ड से परे एक अज्ञात दस्तावेज़ पर भरोसा किया है, जिसे कथित रूप से इंद्रजीत सिंह (जिसका डी.जी.ए.डी. के रूप में बहुत कम कार्यकाल था) द्वारा 31 मार्च, 2017 को बनाया गया गोपनीय नोट बताया गया है। नोट की विषय-वस्तु को यदि जस-की-तस ली जाय, तो यह उचित नहीं है कि बिना किसी सामग्री के सुनी-सुनाई बातों को कैसे रखा जा सकता है। हालाँकि, मामले का प्रासंगिक तथ्य यह है कि उक्त अधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई जांच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी और याचिकाकर्ता ने नियमों के विरुद्ध कार्य करने से इनकार कर दिया था। वास्तव में, उसी अधिकारी के पास बाद के चरण में कोई विकल्प नहीं बचा, बल्कि नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा तैयार किए गए अंतिम निष्कर्षों पर हस्ताक्षर कर दिए। जो भी हो, उक्त नोट की सच्चाई की जांच करने के बजाय, उक्त अधिकारी को याचिकाकर्ता की पीठ पीछे पुनरीक्षण समिति के समक्ष भी बातचीत के लिए बुलाया गया था। उनका कहना है कि यह एक गंभीर दोष है और जिसे याचिकाकर्ता के खिलाफ सामने नहीं लायी जा सकी, उसके आभाव में इसे मौखिक विचारों से किया गया।

वास्तव में, इस न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी शपथ पत्र में दर्ज किया गया है कि अभ्यावेदन समिति के अध्यक्ष को कथित रूप से गोपनीय रूप से कुछ तथ्य बताए गए हैं, जो बाहरी सामग्री के साथ प्रभाव डालने के समान है।

33. उनका कहना कि प्रत्यर्थी की ओर से आक्षेपित कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना, आभासी और बिना किसी प्राधिकार के है और इस प्रकार इसे अपास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने ***शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य, (2017) 9 एस.सी.सी. 1,*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि स्पष्ट मनमानी पर आधारित कोई भी विधायी या प्रशासनिक कार्रवाई तर्कसंगतता की अवधारणा की त्रिकोणीय समझ से प्रभावित होती है। [संदर्भ ***ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (1974) 4 एस.सी.सी. 3***]।

34. इसलिए, उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, याचिकाकर्ता आक्षेपित आदेश को अपास्त करने के लिए इस न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है।

<u>प्रत्यर्थी **की ओर से प्रस्तुतियाँ**</u>

35. जबकि, भारत संघ/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान कें.सर.स्था.अधि. रवि प्रकाश ने प्रस्तुत किया कि 21 मार्च, 2014 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देश और 11 सितंबर, 2015 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन द्वारा पूरक, किसी उपयुक्त

प्राधिकारी को, यदि जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो, किसी सरकारी कर्मचारी को एफ.आर. 56(ञ) या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48(1)(ख) के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, सेवानिवृत्त करने का आत्यंतिक अधिकार प्रदान करता है।

36. उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्येक पुनरीक्षण में, पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार किया जाना चाहिए। 'सेवा रिकॉर्ड' अभिव्यक्ति में सभी प्रासंगिक अभिलेखों को शामिल किया जाएगा और इसलिए पुनरीक्षण ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. डोजियर पर विचार करने तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल में भी मूल्यवान सामग्री हो सकती है। इसी तरह, अधिकारी के काम और प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके द्वारा निपटाई गई फाइलों को देखकर या उसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए किसी भी कागजात या रिपोर्ट से भी किया जा सकता है। यहां तक कि ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. में असंसूचित टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

37. उन्होंने प्रस्तुत किया कि डी.ओ.पी.टी. ने समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन की आवधिक पुनरीक्षण की आवश्यकता पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक हित में सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए या सेवा से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रावधान सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के एफ. आर. 56(ञ), एफ. आर. 56 (आई) और नियम 48 (1)

(बी) में दिए गए हैं। पुनरीक्षण प्रत्येक प्रशासनिक अधिकरण द्वारा की जाने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है।

38. उन्होंने आगे कहा कि डी.ओ.पी.टी. द्वारा जारी किए गए निर्देशों में पुनरीक्षण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों के अभ्यावेदन को संबोधित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की पुनरीक्षण करने के साथ-साथ अभ्यावेदन समिति की संरचना को निर्धारित किया है, ताकि पुनरीक्षण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों के अभ्यावेदन को संबोधित किया जा सके। इस विषय पर निर्देशों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 मार्च, 2014 के कार्यालय ज्ञापन में समेकित किया गया है, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 सितंबर, 2015 के और दिनांक 28 अगस्त, 2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा पूरक किया गया है।

39. उन्होंने प्रस्तुत किया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 21 मार्च, 2014 के अपने कार्यालय ज्ञापन में एफ.आर. 56(ञ), एफ. आर. 56(1) नियमावली के नियम 48 के तहत सरकारी कर्मचारियों की पुनरीक्षण के लिए जारी, अद्यतन और समेकित निर्देश दिए हैं। इसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 11 सितंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा पूरक किया गया, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने विभिन्न स्तरों/श्रेणियों के अधिकारियों के लिए पुनरीक्षण समितियों की संरचना भी निर्धारित की थी। इसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि पुनरीक्षण समिति, जैसा कि वर्तमान

मामले में लागू होता है, की अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव कर सकते हैं। इसमें आगे यह निर्दिष्ट किया कि मुख्य सतर्कता अधिकारी (जो सी.वी.सी. का प्रतिनिधि है) को भी पुनरीक्षण समिति से संबद्ध किया जाना चाहिए। एफ. आर. 56(ञ) के तहत पुनरीक्षण के लिए डी.ओ.पी.टी. के समेकित निर्देश, जैसा कि आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन में निहित है, सी.वी.ओ. या ए.सी.सी. के साथ किसी परामर्श का प्रावधान नहीं करते हैं। सी.वी.ओ., दोनों अवसरों पर पुनरीक्षण समिति के सदस्य थे, जिन्होंने याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति की सिफारिश की थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 28 अगस्त, 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए अपने सभी दिशा-निर्देशों को फिर से समेकित किया है, जिसमें सी.वी.सी./ए.सी.सी. के साथ परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है।

40. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जहां तक सत्यनिष्ठा का संबंध है, निर्देशों में ***एस. रामचंद्र राजू बनाम उड़ीसा राज्य, (1994) पू. (3) एस.सी.सी. 424,*** के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया है। इसलिए, किसी कर्मचारी की सत्यनिष्ठा पर विचार करते समय, किसी कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य या निर्णय जो उचित नहीं प्रतीत होते हैं, उसके खिलाफ प्राप्त शिकायतें, या संदिग्ध संपत्ति लेनदेन, जिसके लिए विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो सकते हैं, को ध्यान में रखा जा सकता है।

41. उन्होंने आगे कहा कि डी.जी.एफ.टी. ने उन 49 अधिकारियों के संबंध में पुनरीक्षण की थी जो आई.टी.एस. से संबंधित थे और उन्हें सरकारी सेवा में बनाए रखने के लिए या अन्यथा पुनरीक्षण के लिए पात्र थे। वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में पुनरीक्षण समिति, जिसमें वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव और सी.वी.ओ. और डी.जी.एफ.टी. शामिल थे, ने आई.टी.एस. से संबंधित 49 अधिकारियों की पुनरीक्षण की और पुनरीक्षण के आधार पर समिति ने एफ. आर. 56(ञ) के तहत याचिकाकर्ता सहित 4 आई.टी.एस. अधिकारियों को सेवानिवृत्ति करने की सिफारिश की। समिति ने नोट किया कि अधिकारियों का पद पर बने रहना जनहित में नहीं है और अधिकारियों के समग्र रिकॉर्ड, अधिकारियों/हितधारकों के बीच उनकी सामान्य प्रतिष्ठा और उनकी संदिग्ध ईमानदारी पर विचार करते हुए, एफ.आर. 56(ञ) के प्रावधानों के तहत सेवा से उनकी सेवानिवृत्ति की सिफारिश की गई थी। अधिकारी के ए.पी.ए.आर. में टिप्पणियों के साथ, याचिकाकर्ता के आचरण के खिलाफ प्रतिपाटन महानिदेशक (डी.जी.ए.डी.) द्वारा प्रस्तुत गोपनीय नोट को उक्त पुनरीक्षण के लिए रिकॉर्ड पर लिया गया था। प्राप्त उक्त शिकायतों का मूल्यांकन एफ. आर. 56(झ) के तहत नामित पुनरीक्षण समिति द्वारा किया गया था। इसके अलावा, नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा को मंजूरी दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता को 10 मई, 2018 को सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

42. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया और इसे सुश्री अरुणा सुंदरराजन, सचिव (दूरसंचार) की अध्यक्षता वाली अभ्यावेदन समिति द्वारा लिया गया और जिसमें सुश्री रचना शाह, संयुक्त सचिव, कैबिनेट सचिवालय और डी.जी.एफ.टी. शामिल थे, उन्होंने उनके मामले को पुनरीक्षण समिति के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण पर पुनर्विचार किया गया और समिति ने उचित परिश्रम के बाद और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के उच्च स्तर के निर्णय लेने में उनका बने रहना जनहित के लिए हानिकारक होगा, उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त करने के अपने फैसले को दोहराया। पुनरीक्षण समिति ने पूर्व डी.जी.ए.डी. के साथ भी बातचीत की, जिन्होंने याचिकाकर्ता के अनैतिक आचरण के बारे में बताया, जैसा कि उन्होंने डी.जी.ए.डी. का प्रभार संभालते समय गोपनीय नोट के द्वारा पहले बताया था।

43. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभ्यावेदन समिति ने याचिकाकर्ता की संदिग्ध सत्यनिष्ठा से संबंधित सभी तथ्यों, डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों, अदालतों के फैसलों, याचिकाकर्ता के प्रासंगिक रिकॉर्ड, मामले की फिर से जांच के बाद विभाग के सुविचारित दृष्टिकोण पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर वाणिज्य विभाग के फैसले को बरकरार रखा, जिससे याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता को

13 जून, 2019 को उनके अभ्यावेदन की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया गया।

44. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 10 मई, 2018 के आदेश और 13 जून, 2019 के अभ्यावेदन की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए अधिकरण के समक्ष कार्यालय ज्ञापन पेश किया। उक्त कार्यालय ज्ञापन को वर्तमान मामले के तथ्यों में उच्चतम न्यायालय के सभी प्रासंगिक निर्णयों पर विचार करने के बाद अधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है और बर्खास्तगी के उक्त आदेश को मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है:

> *"क) याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति सी.वी.ओ. और ए.सी.सी. के साथ अनिवार्य परामर्श के बिना की गई थी;*
>
> *ख) चूँकि याचिकाकर्ता को ए.सी.सी. द्वारा नियुक्त किया गया था, इसलिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को ए.सी.सी. द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।*
>
> *ग) याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है, क्योंकि उसके ए.पी.ए.आर. बहुत अच्छे हैं और उसमें "सुधार की गुंजाइश है" की टिप्पणी के बाद भी पदोन्नत किया गया।*
>
> *घ) दोनों अवसरों पर पुनरीक्षण समिति की संरचना में पूर्व वाणिज्य सचिव श्री अनूप वाधवान और पूर्व डी.जी.एफ.टी. श्री ए. वी. चतुर्वेदी शामिलाती सदस्य थे;*
>
> *ङ) अभ्यावेदन समिति में पहले अवसर पर पूर्व डी.जी.एफ.टी. श्री ए. वी. चतुर्वेदी भी सदस्य थे, जबकि वे पुनरीक्षण समिति के सदस्य भी रहे थे।"*

45. उन्होंने प्रस्तुत किया कि 21 मार्च, 2014 और 11 सितंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में, अधिकारियों के विभिन्न स्तरों/श्रेणियों के लिए पुनरीक्षण समितियों के गठन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि, वर्तमान मामले में लागू पुनरीक्षण समिति की अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय विभाग के सचिव द्वारा किया जा सकता है। इसमें आगे निर्दिष्ट किया गया है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी (जो सी.वी.सी. का प्रतिनिधि है) को भी पुनरीक्षण समिति से संबद्ध किया जाना चाहिए।

46. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के वर्तमान मामले में, दोनों अवसरों पर पुनरीक्षण समितियों की अध्यक्षता मौजूदा वाणिज्य सचिव, अर्थात, प्रथम पुनरीक्षण समिति में सुश्री रीता तेवतिया और द्वितीय पुनरीक्षण समिति में अनूप वधावन ने किया था। यह उनका मामला है कि अनूप वधावन, जो प्रथम पुनरीक्षण समिति के सदस्य थे (जो कि मौजूदा वाणिज्य सचिव के अनुमोदन से गठित किया गया था), पहले अवसर पर वाणिज्य विभाग के अपर सचिव थे, उन्हें दूसरे अवसर पर पुनरीक्षण समिति का प्रमुख होना था, क्योंकि तब तक उन्हें वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जा चुका था। इसलिए, द्वितीय पुनरीक्षण समिति में श्री अनूप वधावन की उपस्थिति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है और किसी भी दुर्भावना को जिम्मेदार ठहराने के लिए याचिकाकर्ता की क्षमता से परे है।

47. उन्होंने प्रस्तुत किया कि जबकि आलोक वर्धन चतुर्वेदी को डी.जी.एफ.टी. के रूप में, वाणिज्य सचिव की मंजूरी से पुनरीक्षण समिति का सदस्य बनाया गया था, क्योंकि वह आई.टी.एस. के लिए काडर प्रबंधन प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस संदर्भ में, यह दोहराया जाना चाहिए कि आई.टी.एस. अधिकारियों के काडर का प्रबंधन डी.जी.एफ.टी. द्वारा किया जाता है और डी.जी.एफ.टी. ही आई.टी.एस. अधिकारियों के सभी सेवा मामलों का अभिरक्षक है। इसलिए, उनके पुनरीक्षण समिति के सदस्य होने के पीछे कोई पक्षपात नहीं माना जा सकता है।

48. उनके अनुसार, सी.वी.ओ. सुश्री अनीता प्रवीण पहले अवसर पर प्रथम पुनरीक्षण समिति की सदस्य थीं और सी.वी.ओ. श्री श्यामल मिश्रा दूसरे अवसर पर सी.वी.सी. के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय पुनरीक्षण समिति के सदस्य थे। एफ.आर. 56(ञ) के तहत पुनरीक्षण के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समेकित निर्देश, जैसा कि आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन में निहित है, सी.वी.ओ. या ए.सी.सी. के साथ किसी परामर्श का प्रावधान नहीं करते हैं। आई.टी.एस. के एस.ए.जी. स्तर पर नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से की जाती हैं। दोनों अवसरों पर याचिकाकर्ता की समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं (मूल पुनरीक्षण बैठक और पुनर्विचार के लिए बाद की पुनरीक्षण बैठक) को वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में फाइल पर अनुमोदित की

गई थी। ए.सी.सी. याचिकाकर्ता के लिए नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है और सी.वी.सी. या ए.सी.सी. के साथ कोई परामर्श अनिवार्य नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा माना और आरोप लगाया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता के तर्क का कोई आधार नहीं है।

49. उन्होंने प्रस्तुत किया कि समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर अभ्यावेदन समिति द्वारा विधिवत विचार किया गया और याचिकाकर्ता के मामले को पुनर्विचार के लिए पुनरीक्षण समिति को वापस भेज दिया गया। तदनुसार, याचिकाकर्ता की दूसरी पुनरीक्षण की गई और दूसरी पुनरीक्षण समिति ने उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त करने के अपने फैसले को दोहराया। इसके बाद, मूल नियमावली के नियम 56 (ञञ) के संदर्भ में दूसरी पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा को अभ्यावेदन समिति के समक्ष रखा गया। याचिकाकर्ता से संबंधित सभी तथ्यों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, अभ्यावेदन समिति ने दूसरी पुनरीक्षण समिति के फैसले को बरकरार रखा और याचिकाकर्ता को 13 जून, 2019 को उनके अभ्यावेदन की अस्वीकृति के बारे में भी सूचित किया गया।

50. उनका कहना यह है कि अभ्यावेदन समिति की संरचना को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसमें सचिव, दूरसंचार विभाग, संयुक्त सचिव, कैबिनेट सचिवालय और कैडर नियंत्रक प्राधिकारी के प्रतिनिधि शामिल हैं। अभ्यावेदन समिति की पहली बैठक के दौरान, कैडर का

प्रतिनिधित्व आलोक वर्धन चतुर्वेदी, डी.जी.एफ.टी. ने किया और अभ्यावेदन समिति की दूसरी बैठक के दौरान, कैडर का प्रतिनिधित्व संयुक्त डी.जी.एफ.टी. (एच.आर.डी.) ने किया। अभ्यावेदन समिति के विचार-विमर्श को इस आधार पर चुनौती देना कि वे डी.जी.एफ.टी. के सदस्य है, वाणिज्य विभाग या डी.जी.एफ.टी. के बाहर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित दो वरिष्ठ अधिकारियों के विवेक पर सवाल उठाने के समान होगा। यह मनगढन्त बात होगी कि अभ्यावेदन समिति के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की समयपूर्व सेवानिवृत्ति को बरकरार रखते हुए डी.जी.एफ.टी. की उपस्थिति से प्रभावित हो सकते हैं। वास्तव में, इसके विपरीत, अभ्यावेदन समिति, जिसमें डी.जी.एफ.टी. एक सदस्य था, ने पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया था।

51. इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट 10 मई, 1974 के कार्यालय ज्ञापन में निहित डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों को डी.ओ.पी.टी. द्वारा समय-समय पर जारी समेकित निर्देशों द्वारा बहुत पहले हटा दिया गया है। इसके अलावा, जब याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया, तो 21 मार्च, 2014 और 11 मार्च, 2015 के कार्यालय ज्ञापन लागू थे। एफ.आर. 56(ञ) के तहत पुनरीक्षण के लिए डी.ओ.पी.टी. के समेकित निर्देश, जैसा कि आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन में निहित है, सी.वी.ओ. या ए.सी.सी. के साथ कोई परामर्श निर्धारित नहीं करते हैं। डी.ओ.पी.एंडटी. ने 28 अगस्त, 2020 को कार्यालय ज्ञापन द्वारा इस विषय पर

समय-समय पर जारी किए गए अपने सभी दिशा-निर्देशों को फिर से समेकित किया है, जिसमें सी.वी.सी./ए.सी.सी. के साथ परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

52. उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, दूसरी पुनरीक्षण समिति ने पूर्व डी.जी.ए.डी. के साथ भी बातचीत की, जिन्होंने 30 मार्च, 2017 को एक गोपनीय नोट द्वारा याचिकाकर्ता के अनैतिक आचरण का समर्थन किया था। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, तथ्यों को गोपनीय रूप से अभ्यावेदन समिति के अध्यक्ष के साथ भी साझा किया गया था। सभी तथ्यों पर पुनर्विचार करने पर, अभ्यावेदन समिति द्वारा अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया और 13 जून, 2019 के आदेश के द्वारा सूचित किया गया।

53. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की 21 मार्च, 2014 और 11 सितंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन में निहित डी.ओ.पी.एंडटी. के निर्देशों के संदर्भ में 48 अन्य आई.टी.एस. अधिकारियों के साथ पुनरीक्षण की गई थी और आरोप के अनुसार चुनिंदा रूप से नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णय के संबंध में फाइल नोटिंग को खारिज कर दिया गया क्योंकि फाइल नोटिंग/पत्राचार में जानकारी में विभिन्न अधिकारियों के विचार और राय शामिल हैं जिन्होंने याचिकाकर्ता सहित एफ.आर. 56(ञ) के तहत पुनरीक्षण किए गए सभी आई.टी.एस. अधिकारियों की पुनरीक्षण की प्रक्रिया में योगदान दिया है। इसलिए, इसे अस्वीकार करना पड़ा और

याचिकाकर्ता को 08 अगस्त, 2018 के पत्र के द्वारा उपयुक्त जवाब दिया गया।

54. श्री प्रकाश ने ***के. कंदास्वामी बनाम भारत संघ और अन्य, ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 277***, के मामले में, उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया कि किसी भी कर्मचारी की ईमानदारी पर विचार करते समय, कर्मचारी द्वारा किए गए कार्यों या निर्णयों, जो उचित प्रतीत नहीं होते हैं, उसके खिलाफ प्राप्त शिकायतें, या संदिग्ध संपत्ति लेनदेन, जो विभागीय कार्यवाही को शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो सकते हैं, को भी ध्यान में रखा जाय।

55. उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपयुक्त नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात वाणिज्य और उद्योग मंत्री (सी.एंडआई.एम.) की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही उन्हें इस निर्देश के साथ सेवा से सेवानिवृत्त किया गया था कि उन्हें तीन महीने की अवधि के लिए उनके वेतन और भत्तों की राशि के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसकी गणना उसी दर से की जाएगी जिस पर वे सेवा से अपनी समयपूर्व सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त कर रहे थे।

56. उन्होंने प्रस्तुत किया कि 11 सितंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन में भी, ***रामचंद्र राजू (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के निबंधनों के अनुसार, सत्यनिष्ठा को पैराग्राफ 5 में परिभाषित किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सरकारी कर्मचारी के अनुचित आचरण की रिपोर्ट भी समय

से पहले सेवानिवृत्ति का आधार बन सकती है। (संदर्भः ***उत्तर प्रदेश राज्य प्रदेश और अन्य बनाम विजय कुमार जैन, (2002) 3 एस.सी.सी. 641***)।

57. उनका मामला यह है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुच्छेद 7 के अनुसार, जो उस समय प्रासंगिक थे, समूह-'ए' के पदों पर आसीन अधिकारियों और ए.सी.सी. द्वारा नियुक्तियों के मामले में, संबंधित मंत्रालय विभाग के सचिव की अध्यक्षता में पुनरीक्षण समिति काडर नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्री (सी.एंडआई.एम.) आई.टी.एस. अधिकारियों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते, समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अनुमोदन देने में सक्षम हैं। इसलिए, ए.सी.सी. द्वारा नियुक्त व्यक्ति की समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश जारी करने से पहले ए.सी.सी. की मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं माना जाता है।

58. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि किसी भी कर्मचारी की ईमानदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सामग्री के मौजूदगी के मामले में सी.वी.सी. का परामर्श, डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों के पैराग्राफ 8 के निबंधनों के अनुसार अनिवार्य नहीं है, क्योंकि राजपत्रित अधिकारियों के मामले में सी.वी.ओ., दोनों पुनरीक्षण समितियों में सदस्य के रूप में संबद्ध था।

59. उन्होंने ***उमेदभाई एम. पटेल, (पूर्वोक्त),*** उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रस्तुत किया गया है

कि यदि लोक सेवक की सेवाएँ सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं हैं, तो अधिकारी को लोक हित में समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

60. उन्होंने प्रस्तुत किया कि 50 वर्ष की आयु पार कर चुके विभिन्न अधिकारियों के मामलों की पुनरीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति ने विभिन्न अधिकारियों के प्रासंगिक सेवा रिकॉर्ड की जांच की और याचिकाकर्ता के मामले की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए सिफारिश की। याचिकाकर्ता के ए.पी.ए.आर. डोजियर की जांच करने पर, यह देखा गया कि याचिकाकर्ता के ए.सी.आर. में अलग-अलग समय पर कई टिप्पणियां की गईं, उनकी ईमानदारी पर संदेह किया गया और उनके कामकाज के बारे में असंतोष व्यक्त किया गया। याचिकाकर्ता विभाग में एक बहुत ही वरिष्ठ और संवेदनशील पद पर था और निर्धारित मानदंडों से किसी भी छोटे से विचलन का विभाग के कामकाज पर प्रभाव पड़ना और देश के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है।

61. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को अपने करियर में किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ा। हालाँकि, तथ्य यह भी है कि वह एक बहुत ही संवेदनशील पद पर थे, जिसका देश के लिए गंभीर वित्तीय निहितार्थ थे और ऐसे उदाहरण हैं जहाँ उनकी ओर से कुछ विचलन देखे गए थे। याचिकाकर्ता के मामले की पुनरीक्षण करने के बाद समिति ने निम्नलिखित राय दी:

"च. श्री एस. एस. दास (आई. टी. एस.-1989) - समिति ने नोट किया कि फाइलों के साथ-साथ ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय श्री दास का इरादा और आचरण बाधक और शंकास्पद रहा है। सत्यनिष्ठा के मामले में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। यह तथ्य उनके ए.पी.ए.आर. डोजियर में प्रविष्टियों से पता चलता है। कुछ मौकों पर, डी.जी.ए.डी. में उनकी पोस्टिंग के विभिन्न कार्यकालों के दौरान, उनके गैर-पेशेवर आचरण को रिकॉर्ड पर भी लिया गया है। एक मामले में श्री दास पर अवज्ञा का आरोप लगाया गया है। अन्य मामलों में, यह बताया गया है कि मामलों को संभालने में अधिकारी का दृष्टिकोण गैर-पेशेवर और सत्यनिष्ठा संदिग्ध रही है।

समिति ने नोट किया कि अधिकारी को हाल ही में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। हालाँकि, यह देखा गया कि पदोन्नति के समय, अधिकारी सतर्कता के दृष्टिकोण से तकनीकी रूप से स्पष्ट था, (पदोन्नति के लिए सतर्कता स्वीकृति मंजूरी देने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के संदर्भ में), अधिकारी को पदोन्नत किया गया था।

समिति ने अधिकारी की संदिग्ध प्रतिष्ठा और आचरण को ध्यान में रखते हुए जनहित में अधिकारी की समयपूर्व सेवानिवृत्ति की सिफारिश की।"

62. उनका कहना यह है कि भारत सरकार (कार्य आवंटन नियम) नियम, 1961 (28 दिसंबर, 2017 को संशोधित) (संक्षेप में "कार्य संचालन नियमावली") के संदर्भ में, भारत सरकार का कार्य मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा किया जाता है। तदनुसार, कार्य संचालन के आवंटन की पहली अनुसूची के संदर्भ में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री आई.टी.एस. का काडर नियंत्रक प्राधिकारी है।

63. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 (3 अप्रैल, 2020 को संशोधित किया गया है) के निबंधनानुसार, ए.सी.सी. से केवल अधिकारी की नियुक्ति, मनोनयन और पदोन्नति के लिए परामर्श किया जाता है, न कि अधिकारी की सेवानिवृत्ति के लिए।

64. उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार 15 जनवरी, 2009 को याचिकाकर्ता को चीन पी.आर. से मेट कोक के आयात से संबंधित सनसेट पुनरीक्षण मामले में निर्धारित समय के भीतर प्रवर्तन अधिसूचना जारी नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए ज्ञापन दिया गया था। वर्ष 1997-98 के लिए ए.पी.ए.आर. में, याचिकाकर्ता के रिपोर्टिंग अधिकारी ने टिप्पणी की थी कि "वह टीम में अच्छा काम करता है लेकिन अकेले बेहतर काम करता है और अनुभव के साथ-साथ नेतृत्व गुण अधिक विकसित होंगे"। याचिकाकर्ता को नीतिगत मुद्दों के प्रति अपने दृष्टिकोण को और अधिक सकारात्मक करने की भी सलाह दी गई थी। इसके अलावा, अवधि 1998-99 के लिए ए.पी.ए.आर. में, याचिकाकर्ता के रिपोर्टिंग अधिकारी ने ईमानदारी कॉलम में टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ए.पी.ए.आर. में 2014-15 की अवधि के लिए, जब याचिकाकर्ता डी.जी.ए.डी. में पदस्थापित था, रिपोर्टिंग अधिकारी ने ईमानदारी के कॉलम में टिप्पणी की कि सुधार की गुंजाइश है। वर्ष 2017 में, जब याचिकाकर्ता संयुक्त डी.जी.एफ.टी. के रूप में डी.जी.ए.डी. में पदस्थापित था और वह 10,000/- रुपये का ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहा था, 30

मार्च, 2017 को याचिकाकर्ता के खिलाफ ए.एस. और डी.जी.ए.डी. से एक गोपनीय नोट प्राप्त हुआ था। नोट में, यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता समय-समय पर आवंटित विभिन्न प्रतिपाटन और सी.वी.डी. मामलों में जांच अधिकारी के रूप में कार्य किया है और तत्कालीन निर्मित सी.वी.डी. प्रकोष्ठ का प्रभारी भी है, जो भारत के खिलाफ अन्य देशों द्वारा शुरू किए गए सी.वी.डी. मामलों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। यह कहा गया है कि हाल के मामले को संभालने में याचिकाकर्ता का समग्र दृष्टिकोण गैर-पेशेवर था, जिसमें गणना और निष्कर्ष कई बार भिन्न थे। इस मामले की प्रक्रिया के दौरान, याचिकाकर्ता ने कुछ सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो डी.जी.ए.डी. के प्रचलित नियमों/परंपराओं के अनुसार स्वीकार्य नहीं थे, और जिन्हें अतीत में किसी अन्य मामले में भी अनुमति नहीं दी गई थी। ए.एस. और डी.जी.ए.डी. ने यह भी कहा था कि 29 मार्च, 2017 को इस मामले में घरेलू उद्योग आवेदकों के कुछ प्रतिनिधियों ने याचिकाकर्ता से मुलाकात की और याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए, जिसमें मामले में कुछ करने के बदले में कुछ अनुग्रह करने की मांग भी शामिल थी। हालांकि, आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, वे इस बारे में लिखित शिकायत देने से हिचक रहे थे।

65. अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एफ.आर. 56(ञ) के तहत 10 मई, 2018 को याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के तौर-तरीके और अनुमोदन डी.ओ.पी.टी. के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार है और इसकी पूरी तरह से

जांच की गई है और सी.ए.टी., प्रधान पीठ, दिल्ली द्वारा अनुसरण की गई है अभ्यावेदन समिति द्वारा बरकरार रखी गई है और इस तरह याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी विधिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसकी सेवा संदिग्ध ईमानदारी के कारण समाप्त कर दी गई है और इस तरह रिट याचिका को खारिज करने की आवश्यकता है।

<u>प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ</u>

66. श्री घोष का यह भी कहना है कि प्रत्यर्थी ने 10 मई, 2018 के आदेश को पारित करते हुए मनमाने ढंग से काम किया है क्योंकि याचिकाकर्ता को अपूरणीय नुकसान पहुँचाने में कोई लोक हित नहीं था- विशेष रूप से तब जब उसकी आधिकारिक साख उसकी ईमानदारी, योग्यता और उसे सौंपे गए सार्वजनिक कर्तव्य के प्रदर्शन में योग्यता को दर्शाती है। वास्तव में, आक्षेपित निर्णय लेने से पहले कोई भी सामग्री मौजूद नहीं थी, कम से कम अनिवार्य सेवानिवृत्ति को उचित ठहराने वाली। किसी भी समय ऐसी कोई भी सामग्री का खुलासा नहीं किया गया जो 10 मई, 2018 के आदेश का आधार बनने वाले *"बाध्यकारी लोक हित"* से संबंधित हो।

67. उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब 1 जून, 2018 को पहला अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, तो याचिकाकर्ता द्वेष की यथार्थता या अतीत के किसी भी उदाहरण किसी भी तथ्य या कारण से पूरी तरह से अनजान था जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को उचित ठहरा सकता है। उक्त अभ्यावेदन को लंबित

रखा गया था। इस बीच में याचिकाकर्ता ने अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किया। उक्त मूल आवेदन और उक्त अभ्यावेदन के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता, आर.टी.आई. अधिनियम के तहत आवेदन द्वारा, 10 वर्षों के ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. प्राप्त करने में आंशिक रूप से सफल रहा, हालांकि, 10 मई, 2018 के आदेश के निर्णय के संबंध में फाइल टिप्पणियों को अस्वीकार कर दिया गया था। सेवा प्रमाण-पत्रों को इंगित करने वाले दस्तावेजों को प्रासंगिक माना गया। आर.टी.आई. आवेदन के जवाब द्वारा प्राप्त खुलासों के आधार पर 3 अगस्त, 2018 को अतिरिक्त अभ्यावेदन दायर की गई। उक्त अभ्यावेदन महत्वपूर्ण था क्योंकि याचिकाकर्ता के मामले में, उन्हें 16 नवंबर, 2017 को ए.सी.सी. की उचित मंजूरी पर एस.ए.जी. में पदोन्नत किया गया था। इसके अलावा, दिसंबर 2017 के अंतिम ए.पी.ए.आर. में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, यह उचित अनुमान था कि 10 मई, 2018 का आदेश याचिकाकर्ता की सेवा प्रमाण पत्र पर आधारित नहीं है। इसका तार्किक परिणाम यह है कि सेवा रिकॉर्ड के बाहर कुछ सामग्री होनी चाहिए थी जिसके कारण 10 मई, 2018 का आदेश दिया गया। उस सामग्री के बाहरी, अप्रासंगिक और रिकॉर्ड से परे होने की संभावना निकट थी।

68. उन्होंने प्रस्तुत किया कि ज्ञापन, असंसूचित ए.पी.ए.आर. और कथित गोपनीय नोट से संबंधित पिछली घटनाओं के अप्रासंगिक संदर्भ, जो पहली बार

सामने आए हैं, का जवाब दिया जाना चाहिए। इसी कारण से, याचिकाकर्ता को 30 अगस्त, 2018 का व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए विवश किया गया था, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ*, महत्वपूर्ण विवरण के साथ ऐसे सभी मामलों पर जवाब दिया गया था और केवल इसी कारण से, ऐसा लगता है कि 2009 में चीन से मेट कोक पर प्रतिपाटन शुल्क से संबंधित मामले में सनसेट रिव्यू (एस.एस.आर.) की जांच शुरू नहीं करने के लिए ज्ञापन जारी न करने से संबंधित पहला आधार हटा दिया गया था। जहां तक एस.एस.आर. पर कार्यवाही शुरू न करने का संबंध है, यह रिकॉर्ड का विषय है कि उक्त निर्णय लोक हित में था और -उस समय संबंधित प्राधिकारी की उचित सहमति मौजूद थी, और ज्ञापन पर याचिकाकर्ता के जवाब के बाद मामला बंद कर दिया गया था। वह अकेली घटना, अन्यथा, याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा, योग्यता, क्षमता और तकनीकी सुदृढ़ता के बारे में राय बनाने का आधार नहीं हो सकती। वास्तव में, याचिकाकर्ता द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सबसे तर्कसंगत और व्यावहारिक था और संबंधित प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके अलावा, उक्त संसूचना उस अवधि से संबंधित है जब याचिकाकर्ता वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य कर रहा था और जहाँ भी उसने सेवा की, वहाँ उसका सेवा प्रमाण-पत्र इतना प्रभावशाली पाया गया कि उसे सरकार के लिए एक परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया।

69. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तर/प्रति-शपथपत्र में पहली बार, यह कहा गया है कि एफ.आर. 56(ञ) में पूरक अभ्यावेदन का कोई प्रावधान नहीं है। यह स्पष्ट रूप से गलत है कि एफ.आर. 56(ञ) अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने और ऐसे निर्णयों पर पुनर्विचार के लिए अभ्यावेदन का सहारा लेने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रणाली का प्रावधान नहीं करता है। अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सरकार को योग्य मामलों में हुए अन्याय को कम करने में सक्षम बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया बाद के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित की गई है जो जून 1969 से समय-समय पर जारी की गई हैं। इस विषय से संबंधित कोई भी कार्यालय ज्ञापन केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत करने को प्रतिबंधित नहीं करता है। वास्तव में, यह किसी भी कारण से रहित है, यदि गैर-विरोधात्मक कार्यवाही में, नए तथ्य जो बाद में सामने आए हैं (पहले अभ्यावेदन के बाद) को सामने नहीं लाया जा सकता है। दसरे पक्ष को भी सुनो का सामान्य सिद्धांत सार्थक सुनवाई को पूर्व निर्धारित करता है जिसे न्यायिक रूप से पढ़ा गया है जिसका अर्थ है कि पक्षपाती व्यक्ति को किसी भी ऐसी चीज का खंडन करने का पूरा अवसर मिलेगा जिसे उसके खिलाफ पढ़ा जा सकता है। जब एफ. आर. 56(ञ) को लागु करने के लिए "कारणों/सामग्री/परिस्थितियों" का खुलासा नहीं किया गया हो, तब पूरक अभ्यावेदन को दायर करने का याचिकाकर्ता का अधिकार और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। केवल अभ्यावेदनों द्वारा वह दूर करने की कोशिश कर रहा था- यदि उसके खिलाफ कोई भी संदेह दूर-दूर तक पाया जा सकता है, क्योंकि एफ.आर. 56(ञ) के लागु करने की वैधता का

मुद्दा प्रत्यर्थी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक "लोक हित" के निष्कर्ष के प्रकटीकरण के संदर्भ में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है।

70. उन्होंने कहा कि 25 अगस्त, 1971 के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि एफ. आर. 56(ञ) का प्रयोग केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है:-

(i) अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए कदाचार के विशिष्ट कृत्यों के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी को सुगम मार्ग के रूप में सेवानिवृत्त करना; या,

(ii) अतिरिक्त कर्मचारियों को कम करने के लिए या छंटनी से संबंधित नियमों और निर्देशों का पालन किए बिना सामान्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के उपाय के रूप में; या

(iii) इस आधार पर कि सरकारी कर्मचारी अपने कार्यवाहक पद पर बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, या किसी उच्च पद पर पदोन्नति के लिए जिसके लिए वह 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 30 वर्ष की सेवा पूरी करने, जैसा भी मामला हो, के बाद पात्र हो सकता है।

71. उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्चतम न्यायालय ने ***अंकित अशोक जालान बनाम. भारत संघ, ए.आई.आर. 2020 एस.सी. 1936,*** में फैसला सुनाया है कि अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत मामले की सामग्री का विश्लेषण नहीं किया जाता है

या उचित समय सीमा का सम्मान नहीं किया जाता है, toतो इसका मतलब यह होगा कि अभ्यावेदन को पेश करने की संरक्षोपाय का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता के मामले में, प्रत्यर्थी द्वारा अपनाई गई अत्यधिक विलंबकारी रणनीति के कारण इस संरक्षोपाय को नकार दिया गया है।

72. उन्होंने प्रस्तुत किया कि ***भारत संघ (यू.ओ.आई.) बनाम जे.एन. सिन्हा और अन्य, एम.ए.एन.यू./एस.सी./0500/1970,*** के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस धारणा पर आधारित था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति में नागरिक परिणाम शामिल नहीं होते हैं और इस निर्णय का अनुसरण ***गुजरात राज्य और अन्य बनाम सूर्यकांत चुनिलाल शाह, एम.ए.एन.यू./एस.सी./0761/1998,*** किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने लोक हित की अवधारणा पर बहुत विस्तार से विचार किया।

73. उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सजा नहीं है क्योंकि इससे सेवा समाप्त नहीं होती है। न्यायिक पुनरीक्षण का सीमित दायरा इस क्षेत्र में निहित है कि ऐसा आदेश कार्यकारी कार्यवाही होने के नाते मनमानेपन से ग्रस्त नहीं होना चाहिए और जो सिद्धांत कार्यकारी कार्यवाही की व्यक्तिपरक संतुष्टि की वैधता निर्धारित करने में न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे को नियंत्रित करते हैं, वे ऐसे मामलों में विधितः लागू होंगे।

74. उनका कहना है कि वर्तमान मामले में ऐसा कोई प्रकटीकरण नहीं है कि संबंधित अधिकारियों ने कथित पुनरीक्षण के समय सभी सेवा रिकॉर्ड या अन्य प्रासंगिक सामग्रियों की जांच की है। शक्ति का बुद्धिरहित प्रयोग कथित प्रथम चरण से ही स्पष्ट है। इस तरह के मामले में विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए निष्पक्षता के उद्देश्य से जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से वह अवधि बताई गई है, जब अनिवार्य सेवानिवृत्ति के उद्देश्य से अधिकारियों की पुनरीक्षण की जा सकती है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने ***बेरियम केमियल्स लिमिटेड और अन्य बनाम कंपनी लॉ बोर्ड, ए.आई.आर. 1967 एस. सी. 295,*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है।

75. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब तक प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता की 50 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पुनरीक्षण करने का कारण संतोषजनक रूप से नहीं दिखाता है, तब तक कोई भी कारण जो याचिकाकर्ता के खिलाफ था, उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

76. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सेवा मामलों में उच्च न्यायालयों की संवैधानिक अधिकार क्षेत्र, ऐसी सभी शक्तियों पर विचार करती है जो कार्यकारी कार्यवाही में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के तहत प्रयोग की जा सकती हैं। ***जे.एन. सिन्हा और अन्य (पूर्वोक्त)*** में निर्धारित इतरोक्ति में जब सीमित न्यायिक पुनरीक्षण की बात की गई है तो गुणागुण पुनरीक्षण अभिव्यक्ति को

विरोधाभासी माना है। [संदर्भ ***सतीश कुमार सिंह बनाम अनिल कुमार यादव और अन्य, अध्यक्ष, यू.पी.पी.एस.सी., इलाहाबाद, एम.ए.एन.यू./यूपी/ 1944/2015***]।

77. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने अपनी संक्षिप्त पृष्ठभूमि में या कहीं और यह स्पष्ट नहीं किया है कि “विशेष रूप से” वह कौन सी सामग्री थी जिसके कारण प्रत्यर्थी ने यह राय बनाई, याचिकाकर्ता के "ईमानदारी पर बार-बार सवाल उठ रहे हैं"। 10 मई, 1974 और 11 सितंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के पैराग्राफ 8 स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि राजपत्रित अधिकारियों के मामलों में, जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति ए.सी.सी. को संदर्भित की जानी है, जहां ईमानदारी की कमी के आधार पर कार्रवाई की जानी है, मामले को ए.सी.सी. के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीवीसी से परामर्श किया जाएगा। वर्तमान मामले में, न तो याचिकाकर्ता की "संदिग्ध सत्यनिष्ठा का निर्धारण करने वाली" कोई सामग्री रिकॉर्ड पर लाई गई थी और न ही सी.वी.सी. से परामर्श किया गया था, जो एक अनिवार्य आवश्यकता है और संभावित मनमानेपन के खिलाफ एक आवश्यक सुरक्षा उपाय है। बैठकों में केवल सी.वी.ओ. की उपस्थिति से ही, सी.वी.सी. के साथ परामर्श की अनिवार्य आवश्यकता पूरी नहीं होगी। किसी सांविधिक निकाय के साथ परामर्श का उद्देश्य, तरीका और प्रक्रिया को केवल सचिव से नीचे के रैंक के विभागीय अधिकारी की उपस्थिति से ही नहीं टाली जा सकती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कर्मचारी की "संदिग्ध सत्यनिष्ठा" के आधार पर एफ. आर. 56(ञ) को लागु

करने के मामलों में सी.वी.सी. के साथ परामर्श करना सद्भावनापूर्ण राय बनाने से पहले पूर्व शर्त है। इसकी अनुपस्थिति में, पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई है।

78. उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में ***द बेरियम केमियल्स लिमिटेड और अन्य (पूर्वोक्त),*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया है। उनका कहना है कि उच्चतम न्यायालय का वर्तमान निर्णय वर्तमान मामले में हर तरह से लागू होता है, क्योंकि सी.वी.सी. से "किसी कर्मचारी की ईमानदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली" "सामग्री की मौजूदगी" के बारे में परामर्श के अभाव में, "ईमानदारी" के अस्तित्व, वैधता और पर्याप्तता पर कोई राय नहीं बनाई जा सकती। यह प्रमुख आक्षेपित कार्रवाई "प्रामाणिक राय" के गठन के लिए विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है।

79. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला कानून दो मामलों में स्पष्ट हैः क) केवल भारत के राष्ट्रपति के पास एफ.आर. 56(ञ) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की शक्तियां निहित हैं; ख) राष्ट्रपति को दी गई सहायता और सलाह मंत्रिमंडल से आनी चाहिए और इस मामले को देखते हुए कि याचिकाकर्ता एस.ए.जी. द्वारा नियुक्त है, उसे दी जाने वाली सहायता और सलाह ए.सी.सी. की होनी चाहिए न कि ए.सी.सी. से कम या अलग किसी अन्य प्राधिकारी की। यदि उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रमुख आक्षेपित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना हो जाता है और केवल इसी आधार पर इसकी वैधता परिपूर्ण जाती है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने

वी. सी. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाम श्रीकांत, ए.आई.आर.2006 एस. सी. 2304, में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा **किया है**।

80. उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय से जो स्पष्ट सिद्धांत निकलता है वह यह है कि एक बार जब कोई आदेश किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है जिसके पास निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं होती है, तो यह अधिकार क्षेत्र के बिना आदेश है और इसलिए यह अमान्य है। परिणामी कार्यवाही के सिद्धांत में यह प्रावधान है कि उस पर आधारित सभी उत्तरभाव्य कार्यवाहियां भी अमान्य होंगी। यह अधिकार क्षेत्र की त्रुटि है जो मामले की जड़ तक जाती है और यह एक असाध्य त्रुटि है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता, एस.ए.जी. (संयुक्त सचिव) रैंक के अधिकारी होने के नाते, केवल उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सेवा से हटाया/समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है। निस्संदेह वर्तमान मामले में उपयुक्त प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति हैं। हालाँकि, अनुच्छेद 74 के तहत उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना आवश्यक है। इस तथ्य को देखते हुए कि एस.ए.जी. रैंक में याचिकाकर्ता की नियुक्ति ए.सी.सी. की सहायता और सलाह पर आधारित है, यह प्रत्यर्थी का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा सेवा अवधि में कटौती से संबंधित कोई भी निर्णय ए.सी.सी. के अनुमोदन द्वारा समर्थित होना चाहिए। 1974 और 1978 के कार्यालय ज्ञापन विशेष रूप से इसके लिए प्रावधान करते हैं। ऐसा न करने के कारण, प्रमुख आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है क्योंकि न तो राष्ट्रपति को

याचिकाकर्ता के लिए कोई सहायता और सलाह दी गई और न ही उन्हें ऐसी सामग्री से अवगत कराया गया था जिसके आधार पर राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए एफ.आर. 56(ञ) को लागु करने के लिए लोक हित का अस्तित्व मौजूद है। वास्तव में, 10 मई, 2018 का प्रमुख आक्षेपित आदेश यह इंगित नहीं करता है कि क्या निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया गया है या राष्ट्रपति के सचिव द्वारा उनके निर्देश पर किया गया है। यदि ऐसा है भी, तो सर्वोत्तम गुप्त सामग्री जिसके कारण मुख्य आक्षेपित आदेश पारित हुआ, क्या वह कभी राष्ट्रपति के समक्ष लाई गई थी या क्या वह उनके लिए भी गुप्त ही रही है।

81. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यह बयान कि डी.जी.एफ.टी. ने आई.टी.एस. से संबंधित 49 अधिकारियों के संबंध में उनके प्रतिधारण करने या अन्यथा सरकारी सेवा में रहने के लिए पुनरीक्षण की, सच नहीं है। आर.टी.आई. के तहत प्राप्त पुनरीक्षण समिति के कार्यवृत्त की प्रति से पता चला है कि केवल 5 चुने गए अधिकारियों की पुनरीक्षण की गई थी और उनमें से 4 की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए सिफारिश की गई थी। यदि सभी 49 अधिकारियों की पुनरीक्षण की जाती, तो कार्यवृत्त में पुनरीक्षण किए गए सभी अधिकारियों के नाम दर्शाए जाते और इसके अलावा, उन सभी के खिलाफ टिप्पणियां उसी तरह दर्ज की जातीं, जैसे उक्त कार्यवृत्त में बनाए रखने के लिए अनुशंसित पांच में से एक के खिलाफ की गई थीं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा पुनरीक्षण के लिए पहले कुछ ही अधिकारियों को चुना गया था।

82. उन्होंने प्रस्तुत किया कि लगभग 20 साल पहले पुनरीक्षण समिति द्वारा *'याचिकाकर्ता की योग्यता और क्षमता या ईमानदारी पर दर्शायी गई विचार'* के रूप में चुनी गई ए.पी.ए.आर. की टिप्पणियाँ न केवल तुच्छ हैं बल्कि और किसी भी तरह से उन्हें ईमानदारी पर नकारात्मक विशेषता या दर्शाया गया नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, वही ए.पी.ए.आर. याचिकाकर्ता को एक उत्कृष्ट अधिकारी के रूप में मूल्यांकन किए हैं। दूसरी पुनरीक्षण समिति द्वारा जिस एकमात्र दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया है, वह एक गोपनीय नोट है जो पुनः सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है और लेखक स्वयं कहते हैं कि *'इसे प्रमाणित करने के लिए कुछ भी नहीं है'*। इसके अलावा, 30 अगस्त, 2018 को अभ्यावेदन समिति को दिया गया याचिकाकर्ता का व्यापक अभ्यावेदन, जिसमें गोपनीय नोट और उस नोट के लेखक के आचरण पर सीधे तौर पर चर्चा की गई थी, को जानबूझकर अभ्यावेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और दूसरी पुनरीक्षण समिति द्वारा उस नोट के लेखक को बचाने और याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत कार्रवाई को जारी रखने के लिए पुनः नजरअंदाज कर दिया गया।

83. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अभ्यावेदन समिति, अपने कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से दर्ज की है कि चूंकि याचिकाकर्ता को हाल ही में यू.पी.एस.सी. और ए.सी.सी. के अनुमोदन से एस.ए.जी. में पदोन्नत किया गया है, इसलिए मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और उचित अनुमोदन प्राधिकारी के

समक्ष रखा जाना चाहिए, जिससे ए.सी.सी. को वापस जाने का संकेत मिलता है। प्रत्यर्थी पुनः मामले को सी.वी.सी. और ए.सी.सी. के समक्ष रखने में विफल रहा है। मामले के प्रतिप्रेषन के बाद, दूसरी पुनरीक्षण समिति ने 30 अगस्त, 2018 के याचिकाकर्ता के व्यापक अभ्यावेदन की जाँच-पड़ताल करने के बजाय, जिसमें इसके हर पहलू को चुनौती देने वाले तथाकथित गोपनीय नोट के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था, याचिकाकर्ता की पीठ पीछे नोट के लेखक के साथ बातचीत करके सबसे अनैतिक काम किया और अपने पहले के निर्णय को दोहराने के लिए उसके संस्करण को सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके अलावा, दूसरी पुनरीक्षण समिति ने उस अधिकारी के साथ बातचीत करना पसंद किया जो केवल 4 महीने के लिए याचिकाकर्ता का रिपोर्टिंग अधिकारी था, लेकिन पिछले अधिकारी के साथ नहीं जिसने उत्कृष्ट रिपोर्ट के साथ दो साल से अधिक समय तक काम की निरीक्षण की थी। याचिकाकर्ता को अनुरोध किए जाने के बावजूद अपने मामले को रखने के लिए सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

84. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि गोपनीय आधार पर तथ्यों को साझा करके अभ्यावेदन समिति के अध्यक्ष पर प्रभाव डाला गया, जिससे अभ्यावेदन समिति की निष्पक्षता और स्वतंत्रता से समझौता हुआ है।

85. उन्होंने आगे कहा कि 2014 और 2015 के समेकित कार्यालय ज्ञापन पुनरीक्षण समितियों की पुनरीक्षण और पुनर्गठन के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई हैं, लेकिन समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न कार्यालय ज्ञापन के अन्य सभी प्रावधानों, यानी 1969, 1974 आदि को 2014 और 2015 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के पार्श्व-टिप्पण के अनुसार बनाए रखा गया है। 2015 के कार्यालय ज्ञापन ने वरिष्ठ चयन बोर्ड के बजाय केवल सचिव के स्तर पर पुनरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया है जैसा कि 1969 के कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक-II में अधिसूचित किया गया था और 1974 के कार्यालय ज्ञापन में दोहराया गया था। 2015 के कार्यालय ज्ञापन में अनुमोदन प्राधिकारी के बारे में चर्चा नहीं की गई है। एस.ए.जी. और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी 1969 के कार्यालय ज्ञापन और 1974 के कार्यालय ज्ञापन (जो कि 1969 के कार्यालय ज्ञापन का केवल विस्तार है) के अनुसार ए.सी.सी. के साथ जारी है, और 2014 के कार्यालय ज्ञापन में इसे दोहराया गया है। इसी तरह, एस.ए.जी. और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए ए.सी.सी. के पास भेजने से पहले सी.वी.सी. से परामर्श की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया गया है, जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है। केवल पुनरीक्षण समिति के गठन में परिवर्तन करने से ए.सी.सी. द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता को नहीं बदलती है और पुनरीक्षण समिति में सी.वी.ओ. की उपस्थिति में सी.वी.सी. के साथ परामर्श की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है जैसा कि 1974 के कार्यालय ज्ञापन में प्रदान किया गया है।

86. उनका कहना है कि आपत्ति पुनरीक्षण समिति का हिस्सा होने के बाद अभ्यावेदन समिति में आलोक वर्धन चतुर्वेदी की उपस्थिति पर है, जिसने स्पष्ट रूप से अभ्यावेदन समिति के समक्ष विभागीय और व्यक्तिगत पक्षपात को उठाया है और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि बैठक के बाद दो महीने से अधिक समय तक अभ्यावेदन समिति के कार्यवृत्त को रोक कर रखा गया था। प्रत्यर्थी के कृत्य गंभीर और असमर्थनीय हो गए थे, क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि अभ्यावेदन समिति के अध्यक्ष पर अभ्यावेदन समिति से बाहर गोपनीय जानकारी साझा करके दबाव और प्रभाव डाला गया है। इसलिए, दोनों समितियों में एक ही व्यक्ति की उपस्थिति प्रशासनिक न्याय का गंभीर उल्लंघन है। वर्तमान मामले में, अभिलेखों की जांच करने और उस पर एक राय बनाने के बजाय, एक अधिकारी जो लंबे समय से विभाग छोड़ चुका है, उसके व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए पिछले दरवाजे से परामर्श लिया गया और इसे आक्षेपित कार्रवाई के लिए औचित्य के रूप में माना गया। इस प्रकार यह एक स्पष्ट मामला है जहां आक्षेपित कार्रवाई का विचार बाहरी है। यह सुस्थापित विधि है कि यदि बाहरी सामग्री को छोड़कर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, तो निर्णय को *"बिना किसी सामग्री के"* माना जाता है।

87. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि दोनों समितियों में एक ही व्यक्ति की उपस्थिति न केवल कार्यवाही को दूषित करती है, बल्कि व्यक्तिगत और विभागीय पक्षपात भी रखती है जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य

से स्पष्ट है कि कुछ जानकारी गोपनीय रूप से अभ्यावेदन समिति के अध्यक्ष के साथ साझा की गई थी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि समिति द्वारा याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार के लिए मामले को पुनरीक्षण समिति को वापस भेजने के बाद अभ्यावेदन समिति के अध्यक्ष पर अनुचित प्रभाव और दबाव डाला गया था। अभ्यावेदन समिति का गठन अभ्यावेदन पर स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार करने और विभागों द्वारा शक्तियों के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए उचित दृष्टिकोण रखने के उद्देश्य से किया गया था। इसलिए, यह मनगढंत बात नहीं है कि अभ्यावेदन समिति के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी डी.जी.एफ.टी./श्रीमान चतुर्वेदी की उपस्थिति से प्रभावित हो सकते हैं। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अभिलेखों की सामग्री को देखा गया था/या कथित रूप से देखा गया था या कथित रूप से अभ्यावेदन समिति के अध्यक्ष के साथ साझा किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि समिति द्वारा मामले को वापस भेजने के बाद। मामले को वापस भेजने के बाद ऐसी सामग्री को साझा करना जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और ऐसा लगता है कि यह व्यक्तिगत राय थी, "वापस भेजने" के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह केवल इसलिए है क्योंकि अभ्यावेदन समिति ने पहली बार में ठोस कारण पाए, उन्होंने उक्त समिति में डी.जी.एफ.टी. की उपस्थिति के बावजूद पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। इसके बाद, जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, अभ्यावेदन समिति के

अध्यक्ष के साथ अप्रकटित जानकारी साझा करके समिति पर दबाव और प्रभाव डाला गया है ताकि उसके दिमाग में जहर घोला जा सके।

88. उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण समिति ने याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड में नकारात्मक महसूस करने वाली सभी बातों को निकाल लिया है ताकि उन्हें आचरण, कार्यात्मक क्षमता और सत्यनिष्ठा के मामले में लगातार खराब प्रतिष्ठा का रंग दिया जा सके, जबकि उसी अवधि के दौरान कई पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा लगातार की गई कई प्रशंसात्मक टिप्पणियों की अनदेखी की गई, जिसमें कम से कम 8 सचिव स्तर के अधिकारी शामिल थे और याचिकाकर्ता को बिना किसी दोष के एक उत्कृष्ट अधिकारी के रूप में मूल्यांकन किया गया है। वास्तव में पुनरीक्षण के आधारों को जानने के बाद, अधिकरण के समक्ष अगस्त 2018 में याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले मूल आवेदन पर विभाग द्वारा दायर जवाब से, याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन समिति को 30 अगस्त, 2018 को एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर किया, जिसमें आधारों की तुच्छ प्रकृति पर टिप्पणी की गई और तत्कालीन अपर सचिव, इंद्रजीत सिंह द्वारा 30 मार्च, 2017 को एक गोपनीय नोट द्वारा लगाए गए निराधार और सुनी-सुनाई आरोपों का खंडन किया गया और साथ ही नोट के लेखक के अनैतिक और शरारती आचरण को भी अधिकारियों के ध्यान में लाया गया। यद्यपि अभ्यावेदन समिति की बैठक 6 सितंबर, 2018 को अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए हुई थी, लेकिन 30 अगस्त, 2018 के अभ्यावेदन को जानबूझकर और

शरारतपूर्ण तरीके से उक्त अभ्यावेदन समिति के समक्ष नहीं रखा गया था और इस तरह उक्त समिति द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी ने मूल आवेदन को दिए अपने जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया है और अभिवाक किया है कि पूरक अभ्यावेदन पर विचार करने की कोई प्रक्रिया नहीं है और इसलिए 30 अगस्त, 2018 के अभ्यावेदन पर अभ्यावेदन समिति द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था। हालांकि, अभ्यावेदन समिति ने याचिकाकर्ता के पहले और प्रारंभिक अभ्यावेदन और याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर भी याचिकाकर्ता के मामले के प्रतिप्रेषण को पुनर्विचार के लिए पुनरीक्षण समिति को भेजने को उचित पाया। याचिकाकर्ता के मामले को अभ्यावेदन समिति द्वारा पुनरीक्षण समिति को वापस भेजे जाने के बाद भी, उक्त पुनरीक्षण समिति ने फिर से जानबूझकर और शरारतपूर्ण तरीके से उक्त अभ्यावेदन की अनदेखी की क्योंकि उक्त अभ्यावेदन ने सभी तुच्छ आधारों को प्रभावी ढंग से ध्वस्त कर दिया और गोपनीय नोट के लेखक द्वारा निभाई गई शरारत को भी सामने लाया जो पुनरीक्षण का मुख्य आधार था। इसके विपरीत, दूसरी पुनरीक्षण समिति ने उस अधिकारी के साथ बातचीत की जिसने बिना विचार किए अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के लिए गोपनीय नोट दिया था। गोपनीय नोट के लेखक के साथ बातचीत करने के अलावा, अब जवाबी शपथ पत्र द्वारा एक नया तथ्य सामने आया कि पुनरीक्षण समिति ने अभ्यावेदन समिति के अध्यक्ष के साथ अभ्यावेदन को खारिज करवाने के लिए, अभ्यावेदन समिति के अध्यक्ष के साथ गोपनीय रूप से कुछ तथ्य साझा करने की हद तक

जाकर बात की है। इससे न केवल अभ्यावेदनों की जांच की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन हुआ है, बल्कि प्रत्यर्थी ने अभ्यावेदन समिति के अध्यक्ष पर अनुचित प्रभाव के उपयोग के तथ्य को भी स्वीकार किया है। अभ्यावेदन की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र समिति के उद्देश्य का प्रत्यर्थी द्वारा घोर उल्लंघन किया गया है जिससे पूरी प्रक्रिया का मजाक उड़ाया गया है। सबसे पहले, जैसा कि स्वीकार किया गया है, प्रत्यर्थी ने 30 अगस्त, 2018 के याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अभ्यावेदन समिति के समक्ष नहीं रखा और दूसरी ओर पुनर्विलोकन के लिए पुनरीक्षण समिति को वापस भेजे जाने के बाद अभ्यावेदन को खारिज करने के लिए अध्यक्ष पर अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया है। दूसरा, अब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि केवल जिस आधार पर याचिकाकर्ता को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया है, वह एक अधिकारी द्वारा दिया गया एक निराधार और अपुष्ट सुनी-सुनाई बात है, जिसने चार महीने से अधिक समय से याचिकाकर्ता के कार्यों की निगरानी भी नहीं की है और जिसे पिछले सभी वर्षों से कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दर्ज याचिकाकर्ता के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए लगातार बदनाम किया गया है। यह स्पष्ट रूप से प्रति-शपथपत्र में बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों से एक ईमानदार अधिकारी को जानबूझकर उत्पीड़न को इंगित करता है। प्रत्यर्थी ने आगे स्वीकार किया है कि सभी चारों अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए केवल वाणिज्य मंत्री से मंजूरी ली गई थी। जबकि अन्य तीन अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे.ए.जी.) में थे

और मंत्री उनकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति को मंजूरी देने में सक्षम हैं, याचिकाकर्ता एस.ए.जी. में एक अधिकारी था, जिसे हाल ही में यू.पी.एस.सी. और ए.सी.सी. की मंजूरी से उक्त ग्रेड में पदोन्नत किया गया था। एस.ए.जी. और उससे ऊपर के अधिकारियों और ए.सी.सी. नियुक्तियों के लिए ए.सी.सी. के अनुमोदन की वैधानिक आवश्यकता के अलावा, वाणिज्य मंत्री याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति को इस सिद्धांत पर मंजूरी देने में सक्षम नहीं थे कि जब कोई उच्च प्राधिकारी पदोन्नति और नियुक्ति को मंजूरी देता है, तो निम्न प्राधिकारी उसकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति को मंजूरी नहीं दे सकता है।

89. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी के इस प्रकथन के संबंध में कि याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा पर विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर टिप्पणी की गई है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने 1997-98, 1998-99 के ए.सी.आर.एस./ए.पी.ए.आर. में सत्यनिष्ठा पर विचार के रूप में पथभ्रष्ट और तुच्छ टिप्पणियां की है। प्रत्यर्थी द्वारा उद्धृत उक्त ए.सी.आर. में की गई टिप्पणियों को, किसी भी कल्पनाशक्ति से, सत्यनिष्ठा पर प्रतिकूल टिप्पणी के रूप में नहीं माना जा सकता है। 1997-98 का ए.सी.आर., अधिकारी को 'उत्कृष्ट' मूल्यांकन करते हुए याचिकाकर्ता के *'समूह अभिविन्यास और नीति अभिविन्यास'* पर टिप्पणी किया है। यह समझ में नहीं आता है कि इसे याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर एक खराब विचार कैसे माना जा सकता है। 1998-99 ए.सी.आर. कहता है *'कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं लेकिन कोई सार नहीं*

मिला' और याचिकाकर्ता को *'उत्कृष्ट'* के रूप में मूल्यांकन किया है। यह वास्तव में उस कार्य वातावरण में ईमानदारी का प्रमाण पत्र है जिसमें याचिकाकर्ता उस समय काम कर रहा था। लेकिन इसे नकारात्मक रूप में लिया गया क्योंकि पुनरीक्षण समिति को 25 वर्षों से अधिक की किसी भी अन्य रिपोर्ट/रिकॉर्ड में कुछ भी प्रतिकूल नहीं मिला है। जहाँ तक 15 जनवरी, 2009 के ज्ञापन का संबंध है, जिसमें याचिकाकर्ता से 2008 में प्रतिपाटन जांच में प्रारंभिक अधिसूचना जारी नहीं करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था, उक्त मामले को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया था, जिससे लोक हित के मामले में याचिकाकर्ता की गहरी और ईमानदार भागीदारी स्थापित हुई और इस मुद्दे की सराहना की गई और उसी समय इसे छोड़ दिया गया। लेकिन समिति ने, अभिलेख पर किसी अन्य प्रतिकूल सामग्री के आभाव में, उत्तर और मुद्दे के समाधान पर ध्यान दिए बिना इसे लेने को प्राथमिकता दी। इन तीन मुद्दों को उठाना अपने आप में प्रत्यर्थी की ओर से अधिकारी के रिकॉर्ड पर किसी भी वास्तविक प्रतिकूल सामग्री के अभाव में अपने पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रिकॉर्ड करने की हताशा को दर्शाता है।

90. जहाँ तक 2014-15 के ए.पी.ए.आर. का संबंध है, यह केवल उच्च ग्रेड के साथ *'उत्कृष्ट'* रिपोर्ट देते समय इसकी पुष्टि या विस्तार किए बिना ईमानदारी के कॉलम में *'सुधार की गुंजाइश है'* लिखा है, जिससे उपरोक्त टिप्पणी

प्रभावहीन हो जाती है। इसलिए, समिति द्वारा भरोसा किया गया एकमात्र दस्तावेज 30 मार्च, 2017 का तथाकथित गोपनीय नोट था, जो एक अधिकारी द्वारा लिखा गया था, जिसने केवल लगभग 4 महीने तक याचिकाकर्ता के काम की निगरानी की थी। उक्त अधिकारी पर अभिलेखों में हेराफेरी करने और अन्य अनैतिक कार्य करने का संदिग्ध आरोप था, जैसा कि याचिकाकर्ता ने 30 अगस्त, 2018 को अपने अभ्यावेदन में बताया था, जिसे प्रत्यर्थी ने आसानी से नजरअंदाज कर दिया था। यहां तक कि उक्त नोट में भी कहा गया है कि *'आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है'*, जिससे यह *"सुनी-सुनाई बात"* लगता है। इसके अलावा, समिति उसी विभाग के पूर्व महानिदेशक की अत्यधिक सराहनीय रिपोर्टों पर भी ध्यान देने में विफल रही, जिन्होंने याचिकाकर्ता को 9.6 ग्रेडिंग दी थी। यहां तक कि संबंधित अवधि के ए.पी.ए.आर. ने अधिकारी पर कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं की है। इसलिए, विशुद्ध रूप से सुनी-सुनाई बातों और एक अधिकारी के पक्षपाती दृष्टिकोण के आधार पर कागज के एक टुकड़े पर निर्भरता, इसे *'सत्यनिष्ठा पर संदेह बढ़ाने'* के रूप में मानना प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अति निकृष्ट कार्य है।

91. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सी.वी.सी. दिशा-निर्देश ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेने की भी अनुमति नहीं देता है। लेकिन प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन और उसमें उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिए बिना ही याचिकाकर्ता के पदत्याग कर देने के अति उग्र कदम के लिए इस तरह के

नोट पर भरोसा करना उचित समझा। जहाँ तक उक्त नोट की सामग्री और उसमें लगाए गए आरोपों का संबंध है, याचिकाकर्ता ने 30 अगस्त, 2018 को अपने व्यापक अभ्यावेदन में सभी आरोपों को व्यापक रूप से समझाया और उनका खंडन किया था। उक्त अभ्यावेदन में यह स्पष्ट रूप से समझाया गया था कि न्यायिककल्प प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, विभिन्न पक्षकारगण द्वारा की गई सभी दलीलों की जांच करना और नामित प्राधिकारी के समक्ष सभी विकल्पों को लाना याचिकाकर्ता का कर्तव्य और जिम्मेदारी थी और ठीक यही किया गया था। लेकिन गोपनीय नोट का उक्त लेखक, विभाग के लिए नया होने के नाते, प्रक्रिया को समझने में विफल रहा और इसके विपरीत अभिलेखों में फेरबदल करने और अधिकारी को डराने-धमकाने की अनैतिक कार्य का सहारा लिया।

92. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन सभी तथ्यों को 30 अगस्त, 2018 के व्यापक अभ्यावेदन में सामने लाया गया था और ठीक यही कारण है कि प्रत्यर्थी ने इस अभ्यावेदन को पूरी तरह से नजरअंदाज करना पसंद किया। पुनरीक्षण और अभ्यावेदन समिति दोनों में एक ही समय में आलोक वर्धन चतुर्वेदी, डी.जी.एफ.टी. की उपस्थिति के कारण पूरी प्रक्रिया से भी समझौता किया गया। ***के. कंदास्वामी (पूर्वोक्त)*** मामले में निर्धारित शर्तों में से कोई भी याचिकाकर्ता के मामले में नहीं पाई गई है। न तो, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई लिखित शिकायत है, न ही प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता के लंबे करियर के किसी भी

बिंदु पर कोई संदिग्ध संपत्ति लेनदेन आदि मिला है, जिससे उनकी ईमानदारी पर सवाल उठें।

93. 2015 का कार्यालय ज्ञापन केवल सचिवों की अध्यक्षता वाली समिति को पुनरीक्षण करने के लिए वरिष्ठ चयन बोर्ड की शक्ति सौंपता है। यह किसी भी तरह से अनुमोदन शक्तियों को नहीं बदलता है या ए.सी.सी. की शक्तियों को किसी अन्य प्राधिकारी को सौंपता है। प्रशासनिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत एक अधीनस्थ निकाय को ए.सी.सी. द्वारा नियुक्त या पदोन्नत अधिकारी की सेवानिवृत्ति तय करने की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा, एस.ए.जी. और उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सी.वी.सी. के साथ परामर्श प्रक्रिया विभागीय सचिवों द्वारा शक्तियों के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए बनाई गई एक सुरक्षोपाय है। 2015 का कार्यालय ज्ञापन उस परामर्श प्रक्रिया को कहीं भी दूर नहीं करता है। राजपत्रित अधिकारियों की समिति में सी.वी.ओ. की उपस्थिति एस.ए.जी. और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए सी.वी.सी. के साथ परामर्श के समान नहीं है। 1969 और 1974 के कार्यालय ज्ञापन स्पष्ट रूप से सुरक्षोपाय के रूप में एस.ए.जी. और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए अंतर करते हैं। किसी विभाग के सी.वी.ओ., जो आम तौर पर एस.ए.जी. स्तर के अधिकारी होते हैं, को समकक्ष और उच्च रैंक के अधिकारियों के संबंध में परामर्श का कार्य नहीं सौंपा जा सकता है। प्रत्यर्थी ने ***उम्मेदभाई एम. पटेल (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का स्पष्ट

रूप से उल्लंघन किया है, जिसमें कहा गया है कि विभागीय जांच से बचने के लिए समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को एक सुगम मार्ग के रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए, जब ऐसा तरीका अधिक वांछनीय हो और यदि गोपनीय रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टियों के बावजूद अधिकारी को पदोन्नति दी जाती है, तो यह तथ्य अधिकारी के पक्ष में जाता है। प्रत्यर्थी इस बात से सहमत है कि यह सच है कि याचिकाकर्ता को अपने कार्यकाल में किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन आगे यह बताया कि तथ्य यह है कि वह एक बहुत ही संवेदनशील पद पर था, जिसका देश के लिए गंभीर वित्तीय निहितार्थ था और ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ उसके द्वारा कुछ विचलन देखे गए थे, बिना यह बताए कि विचलन क्या था। वास्तव में, याचिकाकर्ता के सभी पिछले रिकॉर्ड बहुत उच्च ग्रेड के साथ "उत्कृष्ट" हैं और अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के विश्लेषणात्मक कौशल और निर्णय लेने की योग्यता की सराहना की है। याचिकाकर्ता को हमेशा से संगठन की परिसंपत्ति माना जाता रहा है।

94. उन्होंने द्वितीय पुनरीक्षण समिति की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में निम्नलिखित बातें प्रस्तुत की हैं:-

I. **समिति ने नोट किया कि फाइलों के साथ-साथ मुवक्किलों के साथ व्यवहार करते समय याचिकाकर्ता का इरादा और आचरण अवरोधक और संदिग्ध रहा है-** याचिकाकर्ता के 25 वर्षों से अधिक के पूरे करियर में किसी भी ए.पी.ए.आर. में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है।

वास्तव में, सभी ए.पी.ए.आर./ए.सी.आर., याचिकाकर्ता के रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण को शानदार शब्दों में दर्ज किए हैं। 20 वर्षों से अधिक के सभी ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. का पूरा बयान अधिकरण के समक्ष रखा गया था जिसमें याचिकाकर्ता के व्यवहार की बहुत अधिक सराहना की गई थी। इसलिए, यह ज्ञात नहीं है कि पुनरीक्षण समिति ने इन टिप्पणियों को कहाँ से ली हैं।

II. **याचिकाकर्ता की ईमानदारी के मामले में अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। यह तथ्य उनकी ए.पी.ए.आर. डोजियर प्रविष्टियों से स्पष्ट होता है-** पिछले 25 वर्षों के किसी भी ए.पी.ए.आर. में ईमानदारी पर कोई भी नकारात्मक आरोपण नहीं दिखाई देती है जैसा कि पहले बताया गया है।

III. **कुछ मौकों पर, डी.जी.ए.डी. में याचिकाकर्ता की पोस्टिंग के विभिन्न कार्यकालों के दौरान, उनका गैर-पेशेवर आचरण रिकॉर्ड पर भी लिया गया**-यह सच्चाई से बहुत दूर है। वास्तव में, डीजीएडी में याचिकाकर्ता की पोस्टिंग के दोनों कार्यकालों के सभी ए.पी.ए.आर., याचिकाकर्ता की पेशेवर योग्यता और आचरण को बिना किसी अपवाद के सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा अत्यधिक सराहा गया है और सभी ए.पी.ए.आर. "उत्कृष्ट" रहे हैं। इसलिए, यह केवल एक मनगढंत बात

है या समिति का पक्षपाती दृष्टिकोण है जो किसी भी रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है।

IV. **याचिकाकर्ता को एक मामले में, उस पर अवज्ञा का आरोप लगाया गया था-** यह दूसरी पुनरीक्षण समिति के स्तर पर उठाया गया एक नया आरोप है क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ कभी भी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है। प्रति-शपथपत्र में भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए, यह बयान पुनः समिति की कल्पना की उपज है। यह स्पष्ट है कि विभाग याचिकाकर्ता के खिलाफ एक द्वेष रखता था क्योंकि उसने विभाग द्वारा दबाव डालने और ज़ोर-ज़बर्दस्ती किए जाने के बावजूद 2015-16 में इस न्यायालय के समक्ष काडर पुनरीक्षण के संबंध में एक याचिका को वापस लेने से इनकार कर दिया था। पूरा अति निकृष्ट कार्य एकमात्र अधिकारी को बाहर निकालना है जो इस न्यायालय के समक्ष मामले को वापस लेने के दबाव के आगे नहीं झुके हैं।

V. **अन्य मामलों में, यह बताया गया है कि मामलों को संभालने वाले अधिकारी का दृष्टिकोण गैर-पेशेवर रहा है और सत्यनिष्ठा संदिग्ध है-** यह रिकॉर्ड पर है कि पेशेवर क्षमता, दक्षता और दृष्टिकोण उच्चतम रहा है जिसकी पुष्टि पिछले सभी वर्षों में लगातार रिपोर्टिंग और

पुनरीक्षण अधिकारियों द्वारा की गई है। समिति ने स्पष्ट रूप से इन सभी रिपोर्टों पर से अपनी आंखें बंद कर ली हैं और केवल एक अधिकारी द्वारा दिए गए एक नोट पर ध्यान केंद्रित किया है जिसने चार महीने तक भी याचिकाकर्ता के काम की निगरानी नहीं की थी और न्यायिककल्प कार्यवाही की कोई समझ नहीं थी। इसके अलावा, अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ और अधीनस्थ अधिकारियों पर दबाब डालने के कारण उक्त अधिकारी का आचरण अनैतिक और एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अशोभनीय रहा है। इस तथ्य को सचिव के साथ-साथ समिति के ध्यान में लाया गया। लेकिन दोनों ने इसे नजरअंदाज किया, और पूरी प्रक्रिया याचिकाकर्ता की कीमत पर उक्त अधिकारी को बचाने के लिए संचालित की जाती रही।

VI. **समिति ने नोट किया कि अधिकारी को हाल ही में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि उस समय अधिकारी सतर्कता के दृष्टिकोण से तकनीकी रूप से स्पष्ट था-** गोपनीय नोट 30 मार्च, 2017 का था और 16 नवंबर, 2017 को यू.पी.एस.सी. और ए.सी.सी. के अनुमोदन से एस.ए.जी. को पदोन्नति आदेश जारी किया गया था। यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ इतना गंभीर आरोप था जैसा कि पुनरीक्षण समिति के नोट में सामने आया, तो यह समझ में नहीं आता है कि विभाग को जांच करने और

सी.वी.सी., यू.पी.एस.सी. और ए.सी.सी. को अवगत कराने से कौन रोक रहा था। जबकि याचिकाकर्ता को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में यू.पी.एस.सी. और ए.सी.सी. द्वारा वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर एस.ए.जी. में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया था, कुछ महीनों के भीतर एक सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं पाया।

95. इसलिए, उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, याचिकाकर्ता अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त करना चाहता है।

<u>विश्लेषण</u>

96. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, आक्षेपित आदेश को चुनौती देने वाले श्री घोष की व्यापक प्रस्तुतियाँ निम्नलिखित हैं:-

i. एस.ए.जी. और उससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ एफ. आर. 56 (ञ) को लागू करने के लिए ए.सी.सी. की मंजूरी एक पूर्व शर्त है;

ii. उपरोक्त स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि 21 मार्च, 2014 का कार्यालय ज्ञापन विशेष रूप से 1969 और 1974 के कार्यालय ज्ञापन को संदर्भित करता है, जो प्रावधान करता है कि एफ. आर. 56(ञ) को लागू करने से पहले ए.सी.सी. की मंजूरी अनिवार्य है;

iii. ए.सी.सी. की मंजूरी लेने की आवश्यकता शक्तियों के मनमाने प्रयोग और निर्णय लेने के तरीके के विरुद्ध एक आवश्यक सुरक्षा है। ए.सी.सी. से अनुमोदन लेने की आवश्यकता पूर्ण प्रकटीकरण पर विचार करती है, ताकि इसे एक सुविचारित राय बनाने में सक्षम बनाया जा सके। खुलासा न करना या मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नहीं रखना विषय-वस्तु पर की गई कार्रवाई को निरस्त कर देता है;

iv. मामले में, एफ.आर. 56(ञ) के तहत की गई कार्रवाई "सत्यनिष्ठा की कमी" से संबंधित है, तो सीवीसी से परामर्श किया जाना चाहिए;

v. 10 मई, 1974 के कार्यालय ज्ञापन में विशेष रूप से सी.वी.सी. से परामर्श की आवश्यकता निर्धारित की गई है, यदि ईमानदारी की कमी के कारण कार्रवाई प्रस्तावित है। यह सुस्थापित विधि है कि, यदि विधि किसी चीज को किसी विशेष तरीके से करना विहित करता है, तो अन्य सभी तरीके वर्जित हो जाते हैं;

vi. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को एफ.आर. 56(ञ) के तहत सेवानिवृत्त करने से पहले सी.वी.सी. के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया है;

vii. अधिकरण यह समझने में विफल रहा है कि एफ. आर. 56(ञ) को लागु करने के उद्देश्य से पुनरीक्षण, विधिक रूप से, 50 वर्ष या 55 वर्ष

की आयु में की जानी चाहिए और पुनरीक्षण उक्त आयु की प्राप्ति से छह महीने पहले पूरी की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के मामले में, 55.6 वर्ष की आयु में और बिना किसी प्रतिकूल सामग्री के पुनरीक्षण की गई थी;

viii. वर्तमान मामले में, ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो याचिकाकर्ता के खिलाफ एफ. आर. 56(ञ) के लागु करने को उचित ठहराने के लिए प्रत्यर्थी ने उस पर भरोसा किया है। वास्तव में, संदिग्ध ईमानदारी से संबंधित अवलोकन अभिलेख पर किसी भी सामग्री के बिना है;

ix. अतः, निष्कर्ष यह है कि ए.पी.ए.आर. डोजियर द्वारा समर्थित याचिकाकर्ता पर यह अभ्यारोपण कि सत्यनिष्ठा के मामले में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। याचिकाकर्ता के ए.पी.ए.आर. में प्रतिकूल टिप्पणी के बाद भी उसे ए.सी.सी. की मंजूरी से पदोन्नति दी गई है। विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि एक बार पदोन्नति दिए जाने के बाद, किसी भी नई और प्रतिकूल सामग्री के अभाव में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से तब, जब बाद के ए.पी.ए.आर. में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं पाई गई है, जो याचिकाकर्ता की ओर से ईमानदारी की कमी पर सवाल उठाती हो;

x. एक अधिकारी अर्थात, आलोक वर्धन चतुर्वेदी को तीनों समितियों का हिस्सा बनाया गया था; इस प्रकार, पक्षपात के उचित संदेह ने प्रक्रिया को दूषित कर दिया है;

xi. अधिकरण का आदेश अधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित निर्णयों के संदर्भ में विधि की सुस्थापित स्थिति के विपरीत है।;

97. सबसे पहले, यहां यह कहा जा सकता है कि वास्तव में याचिकाकर्ता की शिकायत 10 मई, 2018 को एफ.आर. 56(ञ) का प्रयोग करके याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने वाले प्रत्यर्थी द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है।

98. हालांकि पक्षकारगण के अधिवक्ता द्वारा कई कार्यालय ज्ञापन पर भरोसा किया गया है, यहां यह कहा जा सकता है कि प्रासंगिक तिथि पर, यानी 10 मई, 2018 को, यह 11 सितंबर, 2015 का कार्यालय ज्ञापन था, जो एफ. आर. 56(ञ) के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में आधार बना रहा। उक्त कार्यालय ज्ञापन विशेष रूप से ***उम्मेदभाई एम. पटेल (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है, किन परिस्थितियों के तहत एक अधिकारी को एफ. आर. 56(ञ) के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

99. यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता ए.सी.सी. द्वारा नियुक्त होने के कारण, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के तहत परिकल्पित की गई पुनरीक्षण समिति की अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव को काडर नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में करना आवश्यक था। इस मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता डी.जी.एफ.टी. के तहत काम कर रहा था, इसलिए वाणिज्य मंत्रालय के सचिव

को पुनरीक्षण समिति का हिस्सा होना आवश्यक था। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि वाणिज्य मंत्रालय का सचिव उस पुनरीक्षण समिति का हिस्सा था जिसने याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया था।

100. यहां यह भी कहा जा सकता है कि श्री घोष के अभिवचनों में से एक यह है कि याचिकाकर्ता को उसकी ईमानदारी पर संदेह करते हुए एफ. आर. 56(ञ) के तहत सेवानिवृत्त किया गया है, वह केवल सी.वी.सी. की सहमति से ही समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता था और वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी कोई सहमति नहीं ली गई है। इस संबंध में श्री घोष द्वारा 10 मई, 1974 के कार्यालय ज्ञापन पर भरोसा किया गया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> *"अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि वह परिशिष्ट-2 की मद 1(क) को गृह मंत्रालय (अब कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग) को भेजे। कार्यालय ज्ञापन सं. 33/13/61- ईएसटीएस (क) दिनांक 23 जून 1969 के कार्यालय ज्ञापन सं. 33/9/78-ईएसटीएस (क) को दिनांक 10 सितंबर, 1971 द्वारा संशोधित किया गया और यह कहना कि पदों पर आसीन राजपत्रित अधिकारियों के मामलों की पुनरीक्षण की प्रक्रिया, जिसके लिए प्रारंभिक नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को संदर्भित है, निम्नानुसार है:*
>
> *"संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक के अधिकारियों के संबंध में वरिष्ठ चयन बोर्ड या अवर सचिव के रैंक से ऊपर लेकिन संयुक्त सचिव या समकक्ष रैंक से नीचे के पदों के संबंध में केंद्रीय स्थापना बोर्ड, जैसा भी मामला हो, अपनी सिफारिशें करेगा, जिन्हें आदेश के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति के समक्ष रखा जाएगा। अपर सचिव, विशेष सचिव और भारत सरकार के*

सचिव रैंक के अधिकारियों के संबंध में, कैबिनेट सचिव आदेश के लिए सीधे मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति को अपनी सिफारिश करेगा। ***<u>जहां सत्यनिष्ठा की कमी के आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित है, वहां मामले को ए.सी.सी. के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श लिया जाएगा।</u>"***

(जोर दिया गया)

101. यद्यपि श्री घोष का प्रस्तुति प्रथम दृष्टया आकर्षक लगता, लेकिन 2015 का कार्यालय ज्ञापन, जिसने उस तारीख को जब याचिकाकर्ता अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ था, अन्यथा कहता है, क्योंकि यह निर्धारित किया गया है कि राजपत्रित अधिकारियों के मामले में सी.वी.ओ. या गैर-राजपत्रित अधिकारी के मामले में उनके प्रतिनिधि को संबद्ध किया जाना चाहिए, यदि ऐसे अधिकारी का रिकॉर्ड उनकी ईमानदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

102. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि सी.वी.ओ. वास्तव में पुनरीक्षण समिति का हिस्सा था जिसने याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया था। इसलिए श्री घोष की इस याचिका को खारिज करने की आवश्यकता है।

103. यह श्री घोष की प्रस्तुतियों में से एक है कि याचिकाकर्ता को ए.सी.सी. द्वारा नियुक्त किए जाने के कारण, याचिकाकर्ता को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आदेश ए.सी.सी. की मंजूरी लेने के बाद ही पारित किया जा सकता था। उक्त अभिवचन बिना किसी गुणागुण के है, क्योंकि श्री रवि प्रकाश का यह कहना सही है कि भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के संदर्भ में,

ए.सी.सी. से केवल अधिकारी की नियुक्ति, मनोनयन और पदोन्नति के लिए परामर्श किया जाता है, न कि अधिकारी की सेवानिवृत्ति के लिए। इसके अलावा, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, समूह-ए पद पर आसीन अधिकारियों और ए.सी.सी. द्वारा नियुक्त अधिकारियों के मामले में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पुनरीक्षण समिति को पारित करना होता है, जिसकी अध्यक्षता काडर नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा की जा सकती है। यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि पुनरीक्षण समिति की अध्यक्षता सचिव ने नहीं की है, जिसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया है।

104. श्री घोष के अभिवचनों में से एक यह है कि पहली पुनरीक्षण समिति के निर्णय की पुनरीक्षण करने वाली दूसरी पुनरीक्षण समिति में अधिकारियों का वही समूह शामिल था, अर्थात, आलोक वर्धन चतुर्वेदी और अनूप वधावन और इस तरह दोनों समितियों में उनकी उपस्थिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। जबकि श्री रवि प्रकाश ने कहा कि आलोक वर्धन चतुर्वेदी डी.जी.एफ.टी. थे और आई.टी.एस. अधिकारियों के काडर प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करते थे और इसलिए दोनों समितियों में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी।

105. हम श्री घोष के इस प्रस्तुति से सहमत नहीं हैं क्योंकि श्री प्रकाश ने ठीक ही कहा है कि दोनों समितियों में आलोक वर्धन चतुर्वेदी की उपस्थिति आवश्यक

थी क्योंकि वे आई.टी.एस. के काडर नियंत्रक प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

106. इसी तरह, अनूप वधावन को पहली पुनरीक्षण समिति में उपस्थित होना आवश्यक था क्योंकि वे एक अपर सचिव थे। जबकि, दूसरी पुनरीक्षण समिति में, वाणिज्य मंत्रालय के सचिव के हैसियत से उनकी उपस्थिति आवश्यक थी क्योंकि उस समय तक वे सचिव बन चुके थे। यह कहा गया है कि दोनों अधिकारियों की उपस्थिति 2014 और 2015 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित निर्देशों के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप थी। इसलिए, दोनों अधिकारियों की उपस्थिति में कोई अवैधता नहीं हो सकती है।

107. श्री घोष की प्रस्तुतियों में से एक यह भी है कि इंद्रजीत सिंह, जिनका डी.जी.ए.डी. के रूप में कार्यकाल बहुत कम था और जिन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ 31 मार्च, 2017 का गोपनीय नोट दिया था, को दूसरी पुनरीक्षण समिति के समक्ष बुलाया गया था और इसके अलावा, समिति ने पहली पुनरीक्षण समिति की सिफारिश को मंजूरी देते समय उनके गोपनीय नोट पर भी भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी साक्ष्य द्वारा पुष्टि किए बिना गोपनीय नोट पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था और ऐसा साक्ष्य केवल अनुश्रुत साक्ष्य माना जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की प्रथम पुनरीक्षण समिति की सिफारिश को

मंजूरी देने के लिए द्वितीय पुनरीक्षण समिति ने अनुश्रुत साक्ष्यों का मूल्यांकन किया है।

108. हमारा विचार है कि श्री घोष का यह प्रस्तुति इस कारण से भी आकर्षक नहीं है कि इंद्रजीत सिंह द्वारा तैयार किया गया गोपनीय नोट अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के साथ-साथ घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित था। गोपनीय नोट की सामग्री को त्वरित संदर्भ के लिए निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> *"हाल के एक मामले को संभालने में उनका समग्र दृष्टिकोण गैर-पेशेवर था, जिसमें गणना और निष्कर्ष कई बार भिन्न थे। इस मामले की प्रक्रिया के दौरान, उन्होंने कुछ सिद्धांतों पर जोर देने की कोशिश की, जो डी.जी.ए.डी. के मौजूदा नियमों/परंपराओं के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं, और जिसे पूर्व में किसी अन्य मामले में अनुमति नहीं दी गई है।*
>
> *कल (29.03.2017), इस मामले में घरेलू उद्योग आवेदकों के कुछ प्रतिनिधियों ने मुझसे मुलाकात की और श्री दास के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जिसमें इस मामले में कुछ करने के बदले में कुछ अनुग्रह की मांग भी शामिल थी। हालांकि, आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, वे इस बारे में लिखित शिकायत देने के लिए अनिच्छुक थे।*
>
> *इसके बावजूद कि आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है, और यहां तक कि कोई लिखित शिकायत भी नहीं है, विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए और श्री दास संगठन के हित में और लोक हित में, जिस तरह से इस मामले को संभाल रहे हैं, उससे यह वांछनीय प्रतीत होता है कि न केवल उन्हें इस मामले की जांच से अलग कर दिया जाए, बल्कि*

तुरंत डी.जी.ए.डी. से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए और किसी गैर-संवेदनशील पद पर तैनात किया जाए। मैं समझता हूँ कि श्री दास डी.जी.ए.डी. में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अधिकारियों में से एक हैं।"

109. इस अर्थ में, इंदरजीत सिंह द्वारा इस तरह से गोपनीय नोट देने का कुछ आधार था। हमने गोपनीय नोट के साथ-साथ गोपनीय नोट के ऊपर पैराग्राफ 41, 52 और 64 में प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाए गए रुख का भी अध्ययन किया है। उपरोक्त पहलू, ए.पी.ए.आर. में प्रतिकूल रिकॉर्डिंग के साथ, विशेष रूप से 2014-2015 के ए.पी.ए.आर. में याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए, निश्चित रूप से गोपनीय नोट की विश्वसनीयता पर विचार करता है, जिसे दूसरी पुनरीक्षण समिति द्वारा याचिकाकर्ता के संबंध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की पिछली सिफारिश की पुष्टि करने के लिए भी ध्यान में रखा गया था।

110. इसके अलावा, इंद्रजीत सिंह के खिलाफ लगाए गए कोई भी आरोप, जिसका उल्लेख ऊपर पैराग्राफ 32 और 88 में किया गया है, कानून में स्वीकार्य नहीं हैं। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इंदरजीत सिंह को इस याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है ताकि यह न्यायालय उन्हें याचिका में उनके खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में शपथपत्र दायर करने के लिए कह सके। इसलिए, दूसरी पुनरीक्षण समिति ने 3 मई, 2019 की अपनी बैठक में उनके द्वारा उजागर किए गए पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि हमने पैराग्राफ 109, 112, 113 और 114 में उल्लेख किया है,

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश करने के लिए, इसलिए, इसके निष्कर्षों को खारिज नहीं किया जा सकता है।

111. श्री घोष की प्रस्तुतियों में से एक यह भी है कि हालांकि याचिकाकर्ता ने 10 मई, 2018 के आदेश के खिलाफ 1 जून, 2018, 24 जुलाई, 2018, 3 अगस्त, 2018 और 30 अगस्त, 2018 के चार अभ्यावेदन पेश किए हैं, लेकिन जब अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने के लिए 7 सितंबर, 2018 को अभ्यावेदन समिति की बैठक हुई, तो उक्त समिति ने अपनी बुद्धि को पुरोबंधित कर लिया, क्योंकि 30 अगस्त, 2018 के अभ्यावेदन को जानबूझकर उसके सामने नहीं रखा गया था और समिति द्वारा केवल 1 जून, 2018 के पहले अभ्यावेदन पर विचार किया गया था। श्री घोष के अनुसार, यह स्पष्टतः विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है, क्योंकि 30 अगस्त, 2018 के व्यापक अभ्यावेदन, जिसमें इंदरजीत सिंह द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया गया है, पर अभ्यावेदन समिति द्वारा विचार नहीं किया गया है।

112. हमने 07 सितंबर, 2018 को अभ्यावेदन समिति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का परिशीलन किया है। उससे, यह पता चलता है कि अभ्यावेदन समिति ने मामले को वापस विभाग को भेज दिया था ताकि याचिकाकर्ता के सिफारिश की पुनः जांच के लिए नामित पुनरीक्षण समिति के पास वापस ले जाया जा सके और फिर इसे उचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जा सके। पुनर्विचार करने पर, दूसरी पुनरीक्षण समिति ने 3 मई, 2019

को याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन समिति के समक्ष 1 जून, 2018 को किए गए अभ्यावेदन को संदर्भित किया था, जिसमें निम्नानुसार कहा गया है:

"क. डी.ओ.पी.टी. के मौजूदा निर्देशों में यह प्रावधान है कि एक अधिकारी को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एफ.आर. 56(ञ) के तहत पुनरीक्षण के बाद लोक हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। जबकि उन्होंने 2013 में 50 वर्ष की आयु प्राप्त की, उन्हें ऐसा करने के लिए किसी भी अधिकार क्षेत्र के बिना, 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 2018 में सेवानिवृत्त किया गया है;

ख. उनका सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट और बेदाग है और उनके खिलाफ कभी कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं है।

ग. वे 1992 में आई.आई.एम. बैंगलोर में सार्वजनिक नीति और प्रबंधन में प्रतिष्ठित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में शामिल होने वाले पहले भारतीय व्यापार सेवा अधिकारी थे और उन्होंने कई शोध प्रबंध और शोध पत्र लिखे हैं;

घ. उनके पर्यवेक्षण अधिकारियों ने हमेशा उन्हें उत्कृष्ट योग्यता और नेतृत्व गुणों के साथ एक अत्यंत विश्वसनीय और जानकार अधिकारी माना है;

ङ. उन्होंने महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श और विवेचन की प्रक्रिया शुरू करने जैसे कुछ अत्यधिक प्रशंसित कार्य किए हैं और एक विशेषज्ञ के रूप में डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भाग लिया है;

च. उन्हें भारत के खिलाफ सभी सब्सिडी-रोधी मामलों को संभालने के लिए डी.जी.ए.डी. (अब डी.जी.टी.आर.) में एक विशेष सी.वी.डी. अंतश्छादन स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी;

छ. उन्हें भारतीय व्यापार सेवा (संयुक्त सचिव ग्रेड) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में दिनांक 16.11.2017 के आदेश के अनुसार, तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था, और उन्हें एम.आई.एच.ए.एन. एसईजेड, नागपुर में

विकास आयुक्त के रूप में पदस्थापित किया गया था। निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी को हाल ही में पदोन्नत किया गया है तो वह उसके पक्ष में जाएगा।

ज. इन सभी वर्षों में उनके विरुद्ध कभी भी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गई या किसी भी कारण से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी गई।

झ. गोपनीय रिपोर्टों में ईमानदारी के कॉलम में हमेशा उसे ईमानदार बताया गया है;

ञ. ऐसे उत्कृष्ट और मेहनती अधिकारी को सेवानिवृत्त करने से कोई लोक हित नहीं होगा, जिसने अपने कार्यरत संगठन में बहुत अधिक योगदान दिया है, जैसा कि उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबंधित ए.पी.ए.आर. में विधिवत दर्ज किया गया है।"

113. दूसरी पुनरीक्षण समिति ने याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अपनी पिछली सिफारिशों की पुनःजांच के दौरान, याचिकाकर्ता के, सेवा रिकॉर्ड, व्यक्तिगत फाइल, गोपनीय नोट और डी.जी.एफ.टी. द्वारा ए.पी.ए.आर. में प्रस्तुत टिप्पणियां सहित अभ्यावेदन की जांच की।

114. उपरोक्त सभी प्रासंगिक सामग्रियों की जांच करने के बाद, दूसरी पुनरीक्षण समिति का विचार था कि याचिकाकर्ता के कुछ ए.पी.ए.आर. में ऐसी टिप्पणियां थीं जो याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर संदेह पैदा करती हैं। विशेष रूप से, 2014-2015 के ए.पी.ए.आर. का भी संदर्भ दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ता के ईमानदारी कॉलम में दर्ज किया गया था, कि *"सुधार की गुंजाइश है"*। यह कहना पर्याप्त है कि, यह टिप्पणी याचिकाकर्ता को भी बताया गया था, हालांकि, इसके खिलाफ कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

115. यहां यह भी कहा गया कि दूसरी पुनरीक्षण समिति ने याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले की फिर से जांच करते हुए डी.जी.ए.डी. (गोपनीय नोट के लेखक) की फाइल की जांच करके गोपनीय नोट की सामग्री की पुष्टि की थी।

116. अंत में, दूसरी पुनरीक्षण समिति ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों को तर्कसंगत नहीं पाया। यह विचार था कि नौकरशाही के वरिष्ठ स्तर पर, अधिकारी की आचरण और कार्य के संदर्भ में उसकी ईमानदारी सर्वोपरि है और इस प्रकार, अधिकारी की ईमानदारी स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए, उसने लोक हित में याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश करने के पहले के फैसले की पुष्टि करने का निर्णय दिया।

117. इसलिए, श्री घोष का अभिवचन, विशेष रूप से 30 अगस्त, 2018 के अभ्यावेदन पर विचार न करने की, जिसमें याचिकाकर्ता ने उसके पैराग्राफ 15 से 17 में, जिसे हम नीचे दोहराए हैं, इंद्रजीत सिंह द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है, मान्य नहीं है। इसके अलावा, जब दूसरी पुनरीक्षण समिति ने भी डी.जी.ए.डी. की फाइल की जांच करके गोपनीय नोट की सामग्री की पुष्टि की है:-

> *"15. ए.एस. और डी.ए. द्वारा अपने नोट में उठाया गया तीसरा मुद्दा मामले में कुछ इच्छुक पक्षकार द्वारा अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति द्वारा पक्ष लेने की मांग के संबंध में कुछ कथित मौखिक शिकायत थी। इस संबंध में यह विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिपाटन जांच प्रकृति में*

अत्यधिक प्रतिकूल है जहां विविध हितों वाले दो समूह जोरदार तरीके से प्रतिस्पर्धा करते हैं। हारने वाले समूह में व्यथित महसूस करने की प्रवृत्ति होती है और कभी-कभी अधिकारियों को धमकी देने या दबाव बनाने या डराने या जांच को पटरी से उतारने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। यह बहुत बार हुआ है और अनुभवी दास इस दबाव को बहुत चतुराई से संभालते थे। दुर्भाग्य से, यह डी.ए. नया होने के कारण, अपने ऊपर आए अत्यधिक दबाव को नहीं संभाल सका और असुविधाजनक अधिकारी को हटाने के लिए उद्योग की एक सुनियोजित रणनीति के आगे झुक गया। डी.ए. स्वयं नोट में दर्ज किया है कि आरोप स्पष्ट रूप से आधारहीन है और कोई भी सबूत उपलब्ध नहीं है। आगे यह नोट देने और अधोहस्ताक्षरित को निदेशालय से बाहर करने के बाद, डी. ए. कुछ दिनों में अधोहस्ताक्षरित द्वारा तैयार किए गए उसी निष्कर्ष को अधिसूचित करने जा रहा है।

16. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कोई गैर-पेशेवर संचालन या हेरफेर होता जैसा कि नोट में आरोप लगाया गया है तो वही निष्कर्ष डी.ए. द्वारा अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को निदेशालय से स्थानांतरित करने के बाद जारी नहीं किया जा सकता था। मामले की जांच की गई और कई स्तरों पर पुनः जांच की गई, जिसमें स्वयं डी.ए. भी शामिल था, जैसा कि उनके नोटों में दर्ज है। लेकिन वे स्पष्ट रूप से निष्कर्षों में कुछ भी गलत नहीं पा सके और तदनुसार, अंतिम निष्कर्ष बिना किसी बदलाव के जारी किए गए। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि पूरी कवायद का निश्चित रूप से तथाकथित मौखिक शिकायत से कोई लेना-देना नहीं था, जो किसी भी मामले में अप्रमाणित और बिना किसी आधार के है जैसा कि स्वयं अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है, लेकिन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत प्रतिशोध लिया गया है। बिना किसी परिवर्तन के उसी निष्कर्ष को जारी करने से यह और भी पुष्ट होता है।

17. यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि तथाकथित मौखिक शिकायत के बावजूद उसी वर्ष के ए.पी.ए.आर. में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी। पिछले वर्ष के ए.पी.ए.आर. 9.6/10 के बहुत उच्च ग्रेड के साथ निदेशालय में अधोहस्ताक्षरित के महत्वपूर्ण योगदान को दर्ज किया है।

इसलिए, मामले को गैर-पेशेवर तरीके से संभालने या ईमानदारी में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार और अकारण हैं।"

118. इसके अलावा, यह तथ्य कि 2014-2015 का ए.पी.ए.आर. ईमानदारी के पहलू पर टिप्पणी किया है कि *"सुधार की गुंजाइश है"*, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा विरोध नहीं किया गया है और जिसे दूसरी पुनरीक्षण समिति द्वारा भी स्वीकार किया गया है और अपने आदेश में दोहराया है, इसलिए यह मानते हुए कि 30 अगस्त, 2018 के व्यापक अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया है, जिसमें, एक हद तक, याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं हैं और ए.एस. एंड डी. ए. (इंद्रजीत सिंह) विभाग में नए होने के कारण, उन पर डाले गए अत्यधिक दबाव को नहीं संभाल सके और असुविधाजनक अधिकारी को हटाने के लिए उद्योग की एक सुनियोजित रणनीति के आगे झुक गए, व्यापक अभ्यावेदन पर विचार न करने का अभिवचन, 10 मई, 2018 के आदेश को अवैध और मनमाना बताती है, स्वीकार नहीं की जा सकती है, खासकर तब, जब याचिकाकर्ता के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ है।

119. यहां यह भी रेखांकित करना उचित है कि याचिकाकर्ता के मामले पर फिर से विचार करने पर दूसरी पुनरीक्षण समिति ने याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के अपने फैसले को दोहराने से पहले, अपने गोपनीय नोट में संदर्भित सामग्री को समझने के लिए ए. एस. एंड डी. ए. (इंदरजीत सिंह) के साथ बातचीत भी की है।

120. श्री घोष का यह भी अभिवाक है कि दूसरी पुनरीक्षण समिति द्वारा ए.एस. एंड डी.ए. (इंदरजीत सिंह) के साथ बातचीत याचिकाकर्ता के समर्थन पीठ पीछे की गई थी। यह अभिवचन भी हमें इस कारण से अपील नहीं करती है कि एफ.आर. 56(ञ) का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना कोई सजा नहीं है और इस तरह इससे कोई कलंक नहीं जुड़ा है। इस अर्थ में, विधि की सुस्थापित स्थिति के अनुसार, याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका देकर विभागीय जांच के कठोर और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं थी।

121. दूसरी पुनरीक्षण समिति ने अपनी राय बनाने से पहले ए.एस. एंड डी.ए. (इंदरजीत सिंह) द्वारा दिए गए गोपनीय नोट पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। अतः, उस अर्थ में, पुनरीक्षण समिति की कार्रवाई प्रामाणिक है और इसे अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित नहीं कहा जा सकता है।

122. श्री घोष ने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिकरण यह समझने में विफल रहा है कि एफ.आर. 56(ञ) के उपयोग करने के उद्देश्य के लिए पुनरीक्षण या तो 50 वर्ष या 55 वर्ष की आयु में की जानी चाहिए और इसे उक्त आयु प्राप्त करने से छह महीने पहले पूरा किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की आयु 55.6 वर्ष यानी 55 वर्ष से अधिक थी और इसलिए उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता था। उक्त प्रस्तुतिकरण बिना गुणागुण का है और ***राजेंद्र सिंह वर्मा (मृतक) द्वारा वि.प्र.***

बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और अन्य एम.ए.एन.यु./एस.सी./1071/2011, के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर अब यह अनिर्णीत विषय नहीं है, जिसमें पैराग्राफ 26 से 29 तक में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

> *26. इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर पक्षकारगण के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है कि क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए अपीलार्थीगण के मामलों में 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले पुनः विचार किया जा सकता था, जब छानबीन समिति ने 17 जुलाई, 2000 को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए उनके मामलों पर पहले ही विचार कर लिया था और उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश नहीं की थी, जिस सिफारिश को उच्च न्यायालय के पूर्ण बैठक द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।*
>
> *27. इस संबंध में मामले के अभिलेख से सामने आने वाले कुछ तथ्यों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 के नियम 27 में प्रावधान किया गया है कि सेवा की शर्तों के संबंध में मामलों के संबंध में जिनके लिए उन नियमों में कोई प्रावधान या अपर्याप्त प्रावधान किया गया है, वर्तमान में लागू नियम, निर्देश या आदेश, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में तुलनीय स्थिति के अधिकारियों और भारत संघ के मामलों के संबंध में सेवा करने वाले अधिकारियों पर लागू होते हैं, ऐसी सेवा की शर्तों को विनियमित करेंगे। इस प्रकार अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 (संक्षेप में 1958 का नियम) का नियम 16(3) दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू होगा। 1958 के नियमों के नियम 16 के खंड (3) को 1972 में प्रतिस्थापित किया गया था जिसमें समयपूर्व सेवानिवृत्ति*

की आयु 50 निर्दिष्ट की गई थी। नियम 16(3), के प्रतिस्थापन के बाद, निम्नानुसार हैः-

> *16(3) केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से और सेवा के किसी सदस्य को कम से कम तीन महीने की पूर्व लिखित सूचना देने के बाद, या ऐसे सूचना के बदले में तीन महीने का भुगतान और भत्ता देने के बाद, उस सदस्य से उस तारीख को लोक हित में सेवा से सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा कर सकती है जिस दिन ऐसा सदस्य अर्हक सेवा के तीस वर्ष पूरा करता है या पचास वर्ष की आयु प्राप्त करता है या उसके बाद किसी भी तारीख को सूचना में निर्दिष्ट किया जाता है।*

इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के उन अधिकारियों की पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्ति के मामले की पुनरीक्षण की जानी चाहिए, जिन्होंने 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, ऊपर उद्धृत 1958 के नियमों के नियम 16(3) के आलोक में।

28. इसी तरह, दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारी के मामले में, दिल्ली न्यायिक सेवा नियम, 1970 के नियम 33 में प्रावधान है कि सेवा की शर्तों के संबंध में ऐसे सभी मामलों के संबंध में जिनके लिए नियमों में कोई प्रावधान या अपर्याप्त प्रावधान किया गया है, उस समय लागू नियम या आदेश, जो भारत संघ के मामलों के संबंध में संबंधित पदों पर आसीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, ऐसी सेवा की शर्तों को विनियमित करेंगे।

*29. दिल्ली न्यायिक सेवा नियम, 1970 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। **इसलिए, मूल नियम 56(ज), जो फिलहाल लागू है और दिल्ली न्यायिक सेवा नियम, 1970 के तहत परिकल्पित संबंधित पदों पर आसीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता***

है. दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले को विनियमित करेगा। मूल नियम 56(ज), जो दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू होता है, निम्नानुसार है:

> ***(ज) इस नियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उपयुक्त प्राधिकारी की, यदि यह राय है कि ऐसा करना लोक हित में है, तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस या ऐसे नोटिस के बदले में तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर उसे सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार होगा:***
>
> > ***(i) यदि वह समूह 'ए' या समूह 'बी' सेवा या पद पर या अधिष्ठायी, स्थायीवत् या अस्थायी अर्हक पद पर हैं और उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया था: 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद;***
> >
> > ***(ii) किसी अन्य मामले में पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद।***
> >
> > ***बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी खंड (ई) में निर्दिष्ट किसी सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, जिसने 23 जुलाई, 1966 को या उससे पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया था।***

यह देखा गया कि एफ.आर. 56(ज) उपयुक्त प्राधिकारी को किसी भी सरकारी कर्मचारी को, जिसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा में प्रवेश किया है, उसे 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार देता है।

(जोर दिया गया)

123. श्री घोष की प्रस्तुतियों में से वह अधिकारी, अर्थात, आलोक वर्धन चतुर्वेदी भी है जो तीनों समितियों अर्थात, पहली पुनरीक्षण समिति, अभ्यावेदन समिति के साथ-साथ दूसरी पुनरीक्षण समिति का हिस्सा रहे हैं और इस प्रकार, पक्षपात का उचित संदेह है जिसने प्रक्रिया को दूषित कर दिया है। इस पर श्री प्रकाश का रुख है कि डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों के अनुसार, अभ्यावेदन समिति में सचिव, दूरसंचार विभाग, संयुक्त सचिव, कैबिनेट सचिव और काडर नियंत्रक प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह कहना पर्याप्त है कि आलोक वर्धन चतुर्वेदी, डी.जी.एफ.टी. के रूप में, आई.टी.एस. के काडर का प्रतिनिधित्व करने वाली अभ्यावेदन समिति में मौजूद थे और दूसरी अभ्यावेदन समिति के दौरान, काडर का प्रतिनिधित्व संयुक्त डी.जी.एफ.टी. द्वारा किया गया था। इस मायने में आई.टी.एस. के प्रतिनिधि के रूप में आलोक वर्धन चतुर्वेदी की उपस्थिति आवश्यक थी। किसी भी मामले में, आलोक वर्धन चतुर्वेदी की उपस्थिति को इस कारण से प्रक्रिया को दूषित करने वाला नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री द्वारा लिया गया है। इसके अलावा, प्रथम पुनरीक्षण समिति, अभ्यावेदन समिति और दूसरी पुनरीक्षण समिति जैसी प्रत्येक समिति में अन्य अधिकारी शामिल थे, जो उच्च पदों पर हैं और इसलिए उनके खिलाफ यह कहने के लिए कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि आलोक वर्धन चतुर्वेदी ने उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्णय लेने के लिए प्रभावित किया है और इसलिए, श्री घोष की यह याचिका भी खारिज किए जाने योग्य है।

124. श्री घोष ने ***आर.पी. कपूर (पूर्वोक्त)*** के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया कि आलोक वर्धन चतुर्वेदी का विभागीय पक्षपात और दुर्भावनापूर्ण आचरण, याचिकाकर्ता के खिलाफ सद्भावना और द्वेष की कमी का स्पष्टतः मामला बनता है। यह कहना पर्याप्त है कि उक्त निर्णय एक आपराधिक गलती का निपटान करते हुए दिया गया था। उक्त निर्णय याचिकाकर्ता द्वारा दं.प्र.सं. 1898 (पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 476 के तहत दायर एक आपराधिक विविध आवेदन का निपटान करते हुए सुनाया गया था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कई मामलों की सहायता से "द्वेष" शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया था ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या उसमें विरोधी पक्षकार ने भा.दं.सं., 1860 की धारा 211 के तहत कोई अपराध किया है और इस तरह, उक्त मामले का एफ.आर., 56 (ञ) के प्रयोग करने से कोई लेना-देना नहीं था।

125. जहाँ तक श्री घोष का यह अभिवाक कि दूसरी पुनरीक्षण समिति ने पूर्व डी.जी.ए.डी. के साथ बातचीत की है, जिन्होंने 13 मार्च, 2017 को एक नोट के द्वारा याचिकाकर्ता के अनैतिक आचरण के बारे में बताया था, जो तथ्य अभ्यावेदन समिति के अध्यक्ष के साथ भी साझा किया गया था, और इस तरह पूरी प्रक्रिया को दूषित कर दिया गया है, वह भी विश्वसनीय नहीं है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता का रुख यह है कि दूसरी पुनरीक्षण समिति के सदस्य डी.जी.ए.डी. से प्रभावित थे, जिन्होंने अभ्यावेदन समिति के

अध्यक्ष के साथ गोपनीय नोट के तथ्यों को भी साझा किया था। विवक्षित रूप से, प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि दूसरी पुनरीक्षण समिति के सदस्य और अभ्यावेदन समिति भी तत्कालीन डी.जी.ए.डी. से प्रभावित थे जिन्होंने दूसरी पुनरीक्षण समिति के साथ गोपनीय नोट की सामग्री को साझा या बातचीत किया था। निश्चित रूप से, डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों के अनुसार, काडर के एक सदस्य को अभ्यावेदन समिति की विचार-विमर्श कार्यवाही में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है और इस तरह, डी.जी.एफ.टी. की उपस्थिति उक्त आवश्यकता के कारण थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकारियों ने अभ्यावेदन समिति के अध्यक्ष के साथ अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ गोपनीय नोट की सामग्री को साझा किया या बातचीत किया था। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता को द्वितीय पुनरीक्षण समिति के सदस्यों के साथ-साथ अभ्यावेदन समिति के सदस्यों को भी इन कार्यवाहियों में पक्षकार बनाने की आवश्यकता थी, ताकि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर उक्त सदस्यों से शपथपत्र प्राप्त किया जा सके कि वे संबंधित डी.जी.एफ.टी. द्वारा प्रभावित हुए हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें वर्तमान याचिका में पक्षकार बनाए जाने की अनुपस्थिति में, श्री घोष का यह अभिवाक कायम नहीं रह सकता है।

126. जहाँ तक श्री घोष के अभिवाक का संबंध है कि याचिकाकर्ता को संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई है, गोपनीय नोट बनाने के बाद, उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता था, वह हमें अपील नहीं कर

रहा है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पदोन्नति और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए तय किए गए मानदंड पूरी तरह से अलग हैं। पदोन्नति के मामले में, पदोन्नति की वास्तविक तिथि से पहले पिछले पांच वर्षों के संबंधित रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाता है। जबकि, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में, संबंधित अधिकारी के पुरे सेवा रिकॉर्ड की जांच की जाती है।

127. इसके अलावा, इस संबंध में विधि सुस्थापित है। ***केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बनाम ओम प्रकाश (2022) 5 एस.सी.सी. 100,*** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 12 से 15 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> *"12. राजस्थान एस.आर.टी.सी. बनाम बाबूलाल जांगीर [राजस्थान एस.आर.टी.सी. बनाम बाबूलाल जांगीर, (2013) 10 एस.सी.सी. 551 : (2014) 2 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 219]], के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में उच्च न्यायालय ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति से पहले की 12 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिकूल प्रविष्टियों पर विचार किया था। बृज मोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य [बृज मोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य, (1987) 2 एस.सी.सी. 188 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल दूसरे प्रतिपादना को नामंजूर किया जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय ने कि "वॉश ऑफ सिद्धांत" पर भी विचार किया यानी ऐसे रिकॉर्ड के आहूत अधिक पूर्व के होने के कारण टिप्पणियां मिट जाएंगी।। इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के*

फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसे प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य [प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य, (2010) 10 एस.सी.सी. 693 : (2011) 1 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 550] के रूप में रिपोर्ट किया गया था और यह प्रेक्षित किया गया कि (बाबू लाल जांगीर मामला [राजस्थान एस.आर.टी.सी. बनाम बाबू लाल जांगीर, (2013) 10 एस.सी.सी. 551:(2014) 2 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 219], एस.सी.सी. पृष्ठ 563-64, पैराग्राफ 22-23)

> *"22. उपरोक्त से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बद्रीनाथ [बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु राज्य, (2000) 8 एस.सी.सी. 395 : 2001 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 13] में दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सही नहीं है और गुरदास सिंह [पंजाब राज्य बनाम गुरदास सिंह, (1998) 4 एस.सी.सी. 92 : 1998 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 1004] में इस न्यायालय की टिप्पणियां कि पदोन्नति या इस प्रभाव के लिए कि पदोन्नति या दक्षता सीमा को पार करने या उच्च पद प्राप्त करने से पहले प्रतिकूल प्रविष्टियों को समाप्त नहीं किया जाता है और जब समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए उस कर्मचारी के मामले पर विचार करने की बात आती है तो कर्मचारी के समग्र प्रदर्शन पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखा जा सकता है।*

23. प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य [प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य, (2010) 10 एस.सी.सी. 693 : (2011) 1 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 550] में दिए गए फैसले के बाद विधि का सिद्धांत स्पष्ट हो गया है यह स्पष्ट हो गया है कि किसी कर्मचारी की पदोन्नति के बाद उससे पहले की प्रतिकूल प्रविष्टियों की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी और जब सरकारी कर्मचारी के मामले को आगे की पदोन्नति के लिए विचार किया जाना है तो इसे मिटा दिया जा सकता है। हालाँकि, इस "वॉश ऑफ सिद्धांत" का कोई उपयोग नहीं होगा जब किसी कर्मचारी के मामले का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है कि क्या वह सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त है या उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की आवश्यकता है। दिया गया तर्क यह है कि चूंकि इस तरह का मूल्यांकन "पुरे सेवा रिकॉर्ड" पर आधारित है, इसलिए पुरानी प्रतिकूल प्रविष्टियों या पुरानी अवधि के रिकॉर्ड को ध्यान में नहीं रखने का कोई सवाल ही नहीं है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि इस तरह के रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जा सकता है, साथ ही साथ पिछली अवधि के सेवा रिकॉर्ड को उचित विश्वसनीयता और महत्व देना होगा। उदाहरण के लिए, कुछ बहुत अधिक पूर्व की प्रतिकूल प्रविष्टियों के विपरीत, जहां आसन्न पिछला रिकॉर्ड अनुकरणीय प्रदर्शन दिखाता है,

हाल के अतीत के ऐसे रिकॉर्ड को नजरअंदाज करना और केवल पुरानी प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर कार्य करना, किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्त करना मनमाने ढंग से सत्ता के प्रयोग का एक स्पष्ट उदाहरण होगा। हालांकि, अगर पुराना रिकॉर्ड किसी व्यक्ति की ईमानदारी से संबंधित है तो यह सरकारी कर्मचारी की समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को सही ठहराने के लिए पर्याप्त हो सकता है।"

13. न्यायिक अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेशों को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर बरकरार रखने वाले कई अन्य निर्णय हैं कि न्यायिक सेवा अन्य सेवाओं के समान नहीं है। न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति अपने संप्रभु कार्यों के निर्वहन में राज्य की ओर से कार्य करता है। न्याय प्रदान करना न केवल एक कठिन कर्तव्य है बल्कि इसे एक पवित्र कर्तव्य का निर्वहन माना गया है, इसलिए यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। राम मूर्ति यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [राम मूर्ति यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2020) 1 एस.सी.सी. 801:(2020) 1 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 245] मामले में यह न्यायालय निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 805, पैरा 6)

"6. ... नियोक्ता की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की न्यायक पुनर्विलोकन की गुंजाइश बेहद संकीर्ण और सीमित है। अगर यह मनमाने या अनुचित आधारों पर आधारित पाया जाता है, दुर्भावना से दूषित है, प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी

करता है, केवल तभी हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश हो सकती है। न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन में, एक अपील प्राधिकारी के रूप में उसी पर निर्णय नहीं दे सकता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं।"

14. इस प्रकार, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने बैकुंठ नाथ दास [बैकुंठ नाथ दास बनाम जिला चिकित्सा अधिकारी, (1992) 2 एस.सी.सी. 299: 1993 एस.सी.सी. (एल. एंड. एस.) 521] में इस न्यायालय के फैसले को न केवल गलत पढ़ा है, बल्कि उसमें निर्धारित सिद्धांतों को गलत तरीके से लागू किया है। प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखा जा सकता है जैसा कि ऊपर उल्लिखित अनेकों निर्णयों में उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय [ओम प्रकाश बनाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 2011 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल. 4388] के आदेश में भी तथ्यात्मक त्रुटि है कि कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है और वर्ष 1990 से वर्ष 2009 तक के ए.सी.आर. या तो अच्छे थे या बहुत अच्छे थे। वास्तव में, स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत ए.सी.आर. का सारांश औसत, संतोषजनक और वास्तव में औसत से कम रिपोर्ट भी दिखाता है।

15. पूरे सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें पदोन्नति से पहले की अवधि के ए.सी.आर. शामिल होंगे। समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश पूरे सेवा रिकॉर्ड के आधार पर पारित किया जाना आवश्यक है, हालाँकि हाल की रिपोर्टों का अपना महत्व होगा।"

128. इसी तरह, ***अरुण कुमार गुप्ता बनाम झारखंड राज्य और अन्य, (2020) 13 एस.सी.सी. 355***, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 15 से 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"वॉश ऑफ सिद्धांत

15. याचीगण द्वारा उठाए गए मुख्य तर्कों में से एक यह है कि चूंकि याचीगण *को विभिन्न उच्च पदों पर पदोन्नत किये गये हैं, इसलिए पदोन्नति से पहले उनका रिकॉर्ड अपनी महत्ता खो दिया और इसका बहुत अधिक महत्व नहीं है। डी. रामास्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य [डी. रामास्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य (1982) 1 एस.सी.सी. 510 : 1982 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 115]में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया है। जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया : (एस.सी.सी. पृष्ठ 513, पैरा 4)*

> *"4. कुछ ही महीने पहले अपीलकर्ता की पदोन्नति हुई थी और उसके बाद अयोग्यता या अक्षमता के बारे में कुछ भी मामूली इंगित नहीं होने के कारण, अपीलकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने के सरकार के आदेश को बनाए रखना असंभव है। तमिलनाडु राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सरकार को अपीलकर्ता के पूरे इतिहास पर विचार करने का अधिकार है, जिसमें उसका वह हिस्सा भी शामिल है जो उसकी पदोन्नति से पहले का था। हम यह नहीं कहते कि किसी सरकारी कर्मचारी के पदोन्नत होने के बाद उसके पिछले इतिहास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाना*

चाहिए। कभी-कभी, पिछली घटनाएं वर्तमान आचरण का आकलन करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन जब वर्तमान आचरण में पदोन्नति पर कोई संदेह नहीं है, तो हम अतीत में अनावश्यक खुदाई करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं।"

16. प्यारे मोहन लाल [प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य, (2010) 10 एस.सी.सी. 693 : (2011) 1 एस.सी.सी. (एल. एंड. एस.) 550] में इस न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें वाश-ऑफ सिद्धांत की अवधारणा पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इस विषय पर संपूर्ण निर्णयज विधि का निपटान करने के बाद निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया : (एस.सी.सी. पृष्ठ 704-706, पैरा 24 और 29)

"24. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह कहने के लिए कानून को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि यदि इस न्यायालय के दो या दो से अधिक निर्णयों के बीच टकराव होता है, तो बड़ी पीठ के फैसले का पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वाश-ऑफ सिद्धांत का सार्वभौमिक अनुप्रयोग नहीं है। सरकारी कर्मचारी के मामले में आगे पदोन्नति के लिए विचार करते समय इसकी प्रासंगिकता हो सकती है, लेकिन ऐसे मामले में नहीं जहां कर्मचारी का मूल्यांकन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है कि क्या वह सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त है या उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की आवश्यकता है, क्योंकि समिति को उसके "पूरे सेवा रिकॉर्ड"

को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयुक्तता का आकलन करना है।

*****

29. विधि प्राधिकारी से मूल्यांकन करते समय कर्मचारी के "पूरे सेवा रिकॉर्ड" पर विचार करने की अपेक्षा करता है कि क्या उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में उसे सूचित नहीं किया गया था और उन प्रतिकूल प्रविष्टियों के बावजूद अधिकारी को पहले पदोन्नत किया गया था। इसके अलावा, बहुत अधिक पहले का भी अधिकारी की ईमानदारी के बारे में प्रतिकूल प्रविष्टि अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए पर्याप्त है। न्यायिक अधिकारी के मामले की जांच करने की आवश्यकता होती है, उसे समाज के अन्य अंगों से अलग मानते हुए, क्योंकि वह एक अलग क्षमता में राज्य की सेवा कर रहा है। न्यायिक अधिकारी के मामले पर माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा विधिवत गठित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा विचार किया जाता है और फिर समिति की रिपोर्ट को पूर्ण न्यायालय बैठक के समक्ष रखा जाता है। पूर्ण न्यायालय बैठक द्वारा मामले पर उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जाता है। इसलिए, बुद्धि का उपयोग न करने या दुर्भावनापूर्ण होने के आरोप लगाने की शायद ही कोई संभावना हो।"

17. अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विषय पर कानून, विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों के मामले में, संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

17.1. न्यायिक अधिकारी के अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्देश देने वाला आदेश दंडात्मक प्रकृति का नहीं होता है।

17.2. न्यायिक अधिकारी के अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्देश देने वाले आदेश का कोई सिविल परिणाम नहीं होता है।

17.3. अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए न्यायिक अधिकारी के मामले पर विचार करते समय न्यायिक अधिकारी के पूरे रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाना चाहिए, हालांकि बाद वाले और अधिक समकालीन रिकॉर्ड को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

17.4. उत्तरभाव्य पदोन्नति का मतलब यह नहीं है कि न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करते समय पहले के प्रतिकूल रिकॉर्ड पर गौर नहीं किया जा सकता है।

17.5. न्यायिक अधिकारियों के मामले में विशेष रूप से ईमानदारी से संबंधित प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में "वाश-ऑफ" सिद्धांत लागू नहीं होता है।

17.6. न्यायालयों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानी और संयम के साथ न्यायिक पुनरीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए कि न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आमतौर पर उच्च न्यायालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (यों) की सिफारिश पर निर्देशित की जाती है।

18. उपरोक्त विधि को ध्यान में रखते हुए अब हम वर्तमान मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करेंगे।"

129. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, श्री घोष ने अपनी दलीलों के समर्थन में, निम्नलिखित निर्णयों पर भी भरोसा किया है:

1) देव दत्त बनाम भारत संघ और अन्य, (2008) 8 एस.सी.सी. 725;

2) भारत संघ बनाम एम. ई. रेड्डी और अन्य (1980) 2 एस.सी.सी. 15;

3) एन.सी. दलवाड़ी बनाम गुजरात राज्य, (1987) 3 एस.सी.सी. 611;

4) श्रीमती एस. आर. वेंकटरमण (पूर्वोक्त);

5) उमेदभाई एम. पटेल (पूर्वोक्त);

6) डी. रामास्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य, (1982) 1 एस.सी.सी. 510;

7) सरोज कुमार दत्ता बनाम भारत संघ और अन्य, 2014 एस.सी.सी. ऑनलाइन कोल. 5034;

8) स्वर्ण सिंह चंद (पूर्वोक्त);

9) बैद्यनाथ महापात्रा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (1989) 4 एस.सी.सी. 664;

10) ए. के. क्रैपक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1969) 2 एस.सी.सी. 262;

11) उड़ीसा राज्य बनाम डॉ. डॉ.(सुश्री) बीणापाणी देई और अन्य, (1967) 2 एस.सी.आर. 625;

12) एस. रामचंद्र राजू (पूर्वोक्त);

13) अमर नाथ चौधरी बनाम ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2002) 2 एस.सी.सी. 290 और

14) एम.एस. बिंद्रा (पूर्वोक्त)।

130. जहां तक ***देव दत्त (पूर्वोक्त)*** के फैसले का संबंध है, यह वह मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि सभी प्रकार की ग्रेड निर्धारण, चाहे "बहुत अच्छी", "अच्छी", "औसत" या "खराब", कर्मचारी को सूचित की जानी चाहिए, ताकि संबंधित कर्मचारी को अपनी ग्रेड निर्धारण में सुधार के लिए अभ्यावेदन करने का अवसर मिल सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विधि की सुस्थापित स्थिति है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता को 2014-2015 के ए.पी.ए.आर.में उसके प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में सूचित किया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ कोई अभ्यावेदन दायर नहीं करने का फैसला किया। इसलिए, इस फैसले की इस मामले के तथ्यों में कोई प्रयोज्यता नहीं होगी।

131. जहाँ तक, ***एम.ई. रेड्डी और अन्य (पूर्वोक्त)*** में निर्णय का संबंध है, यह एक ऐसा मामला है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश उत्पीड़न, मनमाने या दुर्भावना से प्रेरित होकर शक्तियों के आभासी प्रयोग में पारित किया गया है, तो न्यायालय इसे खारिज कर सकता है।

132. यहाँ यह कहा गया है कि श्री घोष द्वारा लगाए गए असद्भावी अभिवाक, वर्तमान मामले के तथ्यों में टिकने योग्य नहीं है, इस साधारण कारण से कि, कि याचिकाकर्ता ने सक्षम अधिकारी के खिलाफ विधिक रूप से असद्भावी आरोप नहीं लगाया है, जिसने याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया है, यानी प्रभारी मंत्री, जिन्होंने राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में आक्षेपित आदेश पारित किया है।

133. यह कहा गया कि भले ही इंद्रजीत सिंह के खिलाफ असद्भावी आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले, उक्त आरोप केवल 30 अगस्त, 2018 के व्यापक अभ्यावेदन में लगाए गए हैं, न कि मूल आवेदन या रिट याचिका में। इसलिए, इससे अभिप्राय नहीं जाना जा सकता है। एक पल के लिए यह मानते हुए कि कि, इससे अभिप्राय जाना जा सकता है, वे सक्षम प्राधिकारी और/या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के खिलाफ नहीं किए जाते हैं। अन्यथा भी, जैसा कि ऊपर दोहराया गया है, याचिकाकर्ता को इंद्रजीत सिंह को मूल आवेदन/रिट याचिका में एक पक्षकार बनाने की आवश्यकता थी, ताकि इंद्रजीत सिंह याचिकाकर्ता द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए असद्भावी आरोपों को सामना कर सकें। यह कहना पर्याप्त है कि यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं हो सकता है कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने के लिए इंद्रजीत सिंह से प्रभावित थे।

134. जहां तक ***एन. सी. दलवाड़ी (पूर्वोक्त)*** के मामले में निर्णय का संबंध है, यह वह मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया जाता है, तो यह सरकार को दिखाना होगा कि पारित आदेश लोक हित में आवश्यक था, अन्यथा आदेश विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण होगा। यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता संयुक्त सचिव के पद पर था, जो नौकरशाही में एक वरिष्ठ सरकारी पद है, यह उम्मीद की जाती है कि अधिकारी की ईमानदारी उसके आचरण और कार्य के संदर्भ में सर्वोपरि है और इस तरह का निर्णय लोक हित में निर्णय लेने से पहले से मान कर चला जाता है।

135. जैसा कि ऊपर बताया गया है, ***श्रीमती एस.आर. वेंकटरमण (पूर्वोक्त)***, के मामले पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी अनधिकृत उद्देश्य के लिए वैवेकिक शक्ति का प्रयोग किया गया है तो कानून में द्वेष के प्रश्न की जांच करना आवश्यक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि वैवेकिक शक्तियों का उपयोग अनधिकृत उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, हालाँकि, यहाँ ऐसा मामला नहीं है कि प्रत्यर्थी ने अपनी शक्तियों का उपयोग अनधिकृत उद्देश्य के लिए किया है। हम ऐसा कहते हैं, जैसा कि पहले ही ऊपर निष्कर्ष निकाला गया है, कि प्रत्यर्थी ने 2014 और 2015 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित डी.ओ.पी.टी. निर्देशों के अनुरूप काम किया है, जो

उस समय मौजूद थे जब प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया था। अतः उक्त निर्णय लागू नहीं होगा।

136. ***उमेदभाई एम. पटेल (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई आदेश किसी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए पारित किया जाता है, तो यह बाहरी विचार पर आधारित नहीं होना चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि आदेश बाहरी विचारों पर आधारित है, तो उसे अपास्त किया जा सकता है। जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों में बाहरी विचार की अभिवाक का संबंध है, हम इस तरह के अभिवाक को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके पूरे सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने की कार्रवाई की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसकी व्यक्तिगत फाइलें, गोपनीय नोट और ए.पी.ए.आर. में डी.जी.एफ.टी. द्वारा उसके खिलाफ की गई टिप्पणियां शामिल हैं। इसलिए, उस अर्थ में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी द्वारा पारित 10 मई, 2018 का आदेश बाहरी विचारों पर आधारित है।

137. जहां तक ***डी. रामास्वामी (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का संबंध है, यह वह मामला था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी कर्मचारी को पदोन्नति दिए जाने के तुरंत बाद उस कर्मचारी के खिलाफ किसी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होने पर, अनिवार्य

सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया जाता है, to यह न्यायोचित नहीं है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए। यह कहना पर्याप्त है कि उक्त निर्णय वर्ष 1982 का है और तब से, इस प्रतिपादना में भारी बदलाव आया है, जैसा कि ऊपर के पैराग्राफ 126, 127 और 128 में उल्लेख किया गया है। इसलिए, भले ही किसी कर्मचारी को उत्तरभाव्य में पदोन्नति दी जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि पहले के प्रतिकूल रिकॉर्ड पर गौर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह निर्णय भी याचिकाकर्ता के मामले में सहायता नहीं करेगा।

138. जहां तक ***सरोज कुमार दत्ता (पूर्वोक्त)*** के मामले में निर्णय का संबंध है, यह वह मामला था, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेष रूप से, उसमें अभ्यावेदन समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, यह विचार दिया था कि समिति ने अपने स्वतंत्र विवेक का उपयोग नहीं किया था और वह भी याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन में शामिल आधारों पर विचार किए बिना। यह कहना पर्याप्त है कि वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभ्यावेदन समिति के साथ-साथ दूसरी पुनरीक्षण समिति ने याचिकाकर्ता के मामले पर सार्थक तरीके से विचार किया है और याचिकाकर्ता के पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के निष्कर्ष पर पहुंचा है। अतः यह निर्णय भी वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा।

139. जहाँ तक ***स्वर्ण सिंह चंद (पूर्वोक्त)*** के मामले में निर्णय का संबंध है, यह वह मामला था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई आदेश विधिक विद्वेष से ग्रस्त है, तो न तो कोई प्रकथन करने की आवश्यकता है और न ही उसके सख्त सबूत पर जोर दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा आदेश अवैध होने के कारण पूरी तरह से असंधार्य होगा। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह कहना पर्याप्त है कि प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश, याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना मनमाना आदेश नहीं है, क्योंकि इसे विधि के सिद्धांतों के अनुसार पारित किया गया है, यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुरूप। इसलिए, यह निर्णय भी याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करेगा।

140. इसी तरह, ***बैद्यनाथ महापात्रा (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को योग्यता और चयन के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो उसके सेवा रिकॉर्ड में समाविष्ट प्रतिकूल प्रविष्टियां, यदि कोई हों, तो अपना महत्व खो देती है। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, उपरोक्त पैराग्राफ 122 और 123 में हमारे निष्कर्ष को देखते हुए, उक्त निर्णय भी लागू नहीं होगा।

141. जहां तक ***एस. रामचंद्र राजू (पूर्वोक्त)*** के मामले में निर्णय का संबंध है, यह वह मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय उन तथ्यों पर विचार किया था

जिसमें याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों की जांच किए बिना खारिज कर दिया गया था और उस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को अपास्त कर दिया गया था। यह कहना पर्याप्त है कि वर्तमान मामले में, प्रथम पुनरीक्षण समिति, अभ्यावेदन समिति, साथ ही दूसरी पुनरीक्षण समिति ने याचिकाकर्ता के पूरे सेवा रिकॉर्ड पर व्यापक रूप से विचार किया है और लोक हित में याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और इस तरह, उक्त निर्णय भी याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करेगा।

142. जहाँ तक ***अमर नाथ चौधरी (पूर्वोक्त)*** के मामले में निर्णय का संबंध है, यह वह मामला था, जिसमें अपीलकर्ता का आंतरिक जांच किया गया था और नतीजतन उसे सेवा से हटा दिया गया था और इस तरह, यह वह मामला नहीं था जिसमें याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले के विपरीत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को उसके पूरे सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था और इस प्रकार, यह निर्णय भी याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करेगा।

143. ***एम.एस. बिंद्रा (पूर्वोक्त)*** मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी कर्मचारी की ईमानदारी के बारे में किसी भी संदेह को केवल अनुमानों के आधार पर नहीं माना जाना चाहिए और इसे एक उचित व्यक्ति के मानक से आंके जाने वाली

संभावना की अधिकता पर आधारित होना चाहिए। यह कहना पर्याप्त है कि वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर अनुमानों के आधार पर सवाल उठाया गया है, क्योंकि सभी समितियां यानी पुनरीक्षण समितियां (प्रथम और द्वितीय), साथ ही अभ्यावेदन समिति ने विस्तार से जांच की है, जिसमें गोपनीय नोट और याचिकाकर्ता के ए.पी.ए.आर. में उनकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाली टिप्पणियाँ शामिल हैं और केवल उनकी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर, याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया था। इसलिए, यह निर्णय भी याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करेगा।

144. श्री घोष द्वारा ***सिंघारा सिंह और अन्य (पूर्वोक्त)*** मामले में भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि यह एक सुस्थापित विधि है कि यदि कोई विधि किसी विशेष तरीके से कुछ करने के लिए विहित करता है, तो अन्य सभी तरीके वर्जित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका यह कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एफ.आर. 56(ञ) का प्रयोग करके याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने से पहले, प्रत्यर्थी को सी.वी.सी. से परामर्श करना चाहिए था और ऐसा न करके, प्रत्यर्थी ने अपनी शक्ति का मनमाने तरीके से प्रयोग किया है। यह कहना पर्याप्त है कि, जैसा कि पहले ही ऊपर अभिनिर्धारित किया गया था कि 2014 और 2015 के कार्यालय ज्ञापन, जो उस तारीख को लागू थे, जब याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप

से सेवानिवृत्त किया गया था, में सी.वी.सी. से परामर्श करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए, यह कहना कि प्रत्यर्थी ने उपरोक्त निर्णय की सहायता से मनमाने तरीके से काम किया है, अपील करने योग्य नहीं लगता है और इसलिए, यह याचिकाकर्ता की सहायता नहीं करेगा।

145. इसी तरह, ***न्यायमूर्ति आर.ए. मेहता (सेवानिवृत्त) और अन्य (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया है ताकि "परामर्श" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया जा सके ताकि यह तर्क दिया जा सके कि प्रत्यर्थी ने सी.वी.सी. के साथ कोई "परामर्श" नहीं किया था और इस तरह प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है। जैसा कि हम पहले ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि 2014 और 2015 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित निर्देशों के संदर्भ में सी.वी.सी. के साथ "परामर्श" अनिवार्य नहीं था, यह निर्णय भी याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करेगा।

146. ***मोहिंदर सिंह गिल और अन्य (पूर्वोक्त)*** रिलायंस के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया है यह तर्क देने के लिए कि मूल आवेदन में, यह प्रत्यर्थी का मामला था कि याचिकाकर्ता की ईमानदारी "स्पष्ट नहीं थी", जबकि, वर्तमान याचिका में, यह प्रत्यर्थी का मामला है कि याचिकाकर्ता की "आचरण और कार्यात्मक क्षमता" के मामले में खराब प्रतिष्ठा थी और इस तरह याचिकाकर्ता का यह दृष्टिकोण ***मोहिंदर सिंह गिल और अन्य***

(पूर्वोक्त) में निर्धारित कानून के विरुद्ध है। यह कहना पर्याप्त है, जैसा कि पहले ही ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए एफ.आर. 56(ञ) को लागू करते समय, प्राधिकारी को कर्मचारी का संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड देखना होता है और यहां तक कि एक भी प्रतिकूल टिप्पणी एफ.आर. 56(ञ) को लागू करने का कारण बन सकती है। यह कहना वर्तमान मामले में भी पर्याप्त है कि, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के 1 जून, 2018 के अभ्यावेदन के साथ-साथ उनके संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के बाद, याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया था। इसलिए, यह निर्णय भी याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करेगा।

147. श्री घोष ने ***शायरा बानो (पूर्वोक्त)*** और ***ई.पी. रोयप्पा (पूर्वोक्त)*** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया है और यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की आक्षेपित कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना, आभासी और बिना किसी प्राधिकार का है और इस तरह अपास्त करने योग्य है। यह कहना पर्याप्त है कि श्री घोष का यह तर्क भी इस कारण से खारिज करने योग्य है कि जैसा कि पहले ही ऊपर अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि प्रत्यर्थी द्वारा की गई कार्रवाई 2014 और 2015 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित निर्देशों के अनुरूप है और इस तरह यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने मनमाने और आभासी तरीके से काम किया है और इस तरह ये निर्णय भी याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करेंगे।

148. ***अंकित अशोक जालान (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है और यह तर्क दिया गया कि यदि अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत सामग्रियों का विश्लेषण नहीं किया जाता है या अभ्यावेदन को उचित समय-सीमा के भीतर सम्मानित नहीं किया जाता है, toतो इसका मतलब यह होगा कि अभ्यावेदन को प्रस्तुत करने की सुरक्षा का उल्लंघन किया गया है। यह कहना पर्याप्त है कि 1 जून, 2018 के याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन की प्रत्यर्थी द्वारा विस्तार से जांच की गई है और अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद भी, अभ्यावेदन समिति ने याचिकाकर्ता के मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले को दूसरी पुनरीक्षण समिति को वापस भेज दिया था। दूसरी पुनरीक्षण समिति उचित विचार-विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि याचिकाकर्ता का मामला अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए उपयुक्त था। इसलिए, श्री घोष का यह अभिवाक भी खारिज किए जाने योग्य है और इस तरह उपरोक्त निर्णय भी उनकी सहायता नहीं करेगा।

149. ***जे.एन. सिन्हा और अन्य (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है और यह तर्क दिया गया कि ***जे.एन. सिन्हा और अन्य (पूर्वोक्त)*** मामले में निर्णय इस धारणा पर आधारित था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति में सिविल परिणाम शामिल नहीं हैं, हालांकि पीड़ित पक्षकार के लिए यह तर्क कि सरकार द्वारा बनाई गई राय संपार्श्विक आधारों पर आधारित है या यह मनमाना निर्णय है, अनिर्णीत है। उनका तर्क है कि इस फैसले का

अनुसरण उच्चतम न्यायालय द्वारा ***सूर्यकांत चुनिलाल शाह (पूर्वोक्त)*** के मामले में किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर नहीं रखा जा सकता है और उच्च न्यायालय(यों) या उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों में भलीभाँति हस्तक्षेप कर सकते हैं, यदि वे संतुष्ट हैं कि पारित किया गया आदेश:- (क) दुर्भावनापूर्ण, (ख) बिना किसी साक्ष्य के या (ग) मनमाना है। विशेष रूप से, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो इस तरह की टिप्पणियों का भी प्रभाव समाप्त हो जाता है। यद्यपि हम इस बात से सहमत हैं कि उपरोक्त प्रतिपादना विधि का स्थापित सिद्धांत हैं, तथापि, वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार किया है और उसी के अवलोकन के बाद ही, तीनों समितियां इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की आवश्यकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश मनमाने तरीके से पारित किया गया है और इस तरह, ये निर्णय भी याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करेंगे।

150. श्री घोष ने ***द बेरियम केमियल्स लिमिटेड और अन्य (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है और यह तर्क दिया कि

किसी भी कर्मचारी की ईमानदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सामग्री के मौजूदगी के बारे में सी.वी.सी. के साथ परामर्श के आभाव में, मौजूदगी, वैधता और पर्याप्तता के बारे में कोई राय नहीं बनाई जा सकती है और इस तरह प्रत्यर्थी की आक्षेपित कार्रवाई प्रामाणिक राय बनाने के लिए विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है। यह कहना पर्याप्त है कि श्री घोष का यह अभिवाक अपील नहीं कर रही है, सबसे पहले, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करते समय प्रत्यर्थी को सी.वी.सी. से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं थी और दूसरा, जैसा कि पहले ही ऊपर विस्तार से उल्लेख किया गया है कि तीनों समितियों ने पूर्व डी.जी.ए.डी. द्वारा दायर गोपनीय रिपोर्ट सहित याचिकाकर्ता के पूरे सेवा रिकॉर्ड का गहन अध्ययन किया है और उसके बाद ही प्रत्यर्थी ने 10 मई, 2018 के आदेश के निबंधनों के अनुसार याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का फैसला किया था और इस प्रकार, यह निर्णय भी इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

151. उन्होंने ***सतीश कुमार सिंह (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि नियुक्ति की ओर ले जाने वाली कोई प्रक्रिया कानून के उद्देश्य और प्रयोजन से संबंधित प्रासंगिक सामग्री पर गौर करने में विफल रही है या अप्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा है, तो ऐसा निर्णय आधिकारिक मनमानेपन के आधार पर दूषित माना जाएगा। यह

कहना पर्याप्त है कि यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में इस कारण से लागू नहीं होगा क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश में याचिकाकर्ता के पूरे सेवा रिकॉर्ड सहित सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखा गया था और इस तरह से यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय मनमाने तरीके से और किसी भी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखे बिना लिया गया है।

152. उन्होंने ***वी.सी. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है और यह तर्क दिया कि अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला कानून दो कारणों से स्पष्ट है (क) केवल भारत के राष्ट्रपति के पास एफ.आर. 56(ञ) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की शक्तियां निहित हैं और (ख) राष्ट्रपति को दी गई सहायता और सलाह मंत्रिमंडल से आनी चाहिए और इस मामले को देखते हुए कि याचिकाकर्ता एस.ए.जी. द्वारा नियुक्त है, उन्हें दी गई सहायता और सलाह ए.सी.सी. से आई होनी चाहिए न कि ए.सी.सी. से कम या अलग किसी अन्य प्राधिकारी से। इसलिए, एक बार जब कोई आदेश किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, जिसके पास निर्णय देने की शक्ति नहीं होती है, तो यह अधिकार क्षेत्र के बिना आदेश होता है, इसलिए यह अमान्य है। यह कहना पर्याप्त है कि ए.सी.सी. से केवल अधिकारी की नियुक्ति, मनोनयन और

उन्नयन के लिए परामर्श किया जाता है, न कि उसकी सेवानिवृत्ति के लिए। अतः यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा।

153. ***ए.के. क्राईपक और अन्य (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी भरोसा किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि यदि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय की हत्या को रोकना है तो ऐसे नियमों को प्रशासनिक जांचों पर भी लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रशासनिक जांच में अनुचित निर्णय का प्रभाव न्यायिककल्प जांच में निर्णय की तुलना में अधिक दूरगामी पड़ता है और यदि किसी न्यायालय में शिकायत की जाती है कि नैसर्गिक न्याय के कुछ सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, तो न्यायालय को यह तय करना चाहिए कि उस मामले के तथ्यों पर उचित निर्णय के लिए उस नियम का पालन करना आवश्यक था या नहीं।

154. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रशासनिक जांच में भी अनुचित निर्णय नहीं हो सकता है। तथापि, वर्तमान मामले में, जैसा कि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्यर्थी ने मनमाना निर्णय नहीं लिया है और यह विधि की भी सुस्थापित स्थिति है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, और इस प्रकार, उक्त निर्णय भी वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा।

155. श्री घोष ने ***डॉ. (सुश्री) बिणापाणी देई और अन्य (पूर्वोक्त)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भी सहायता ली है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी अधिकारी को "अच्छे और पर्याप्त कारणों" के अलावा सेवानिवृत्ति से पहले पद से नहीं हटाया जा सकता है और यह प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति को, जिसके खिलाफ जांच की जा रही है, अपना पक्ष रखने या बचाव करने का अवसर दे और प्राधिकारी के पास मौजूद किसी भी साक्ष्य को सही करने या उसका खंडन करने का अवसर दे, जिस पर उसके पूर्वाग्रह के लिए भरोसा किया जा रहा है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि राज्य को लोक सेवक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का अधिकार है, जो सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन जब वह व्यक्ति दावे पर विवाद करता है, तो उसे राज्य के मामले के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उसके प्रतिकूल निर्णय लेने से पहले उसे उस मामले से निपटने का उचित अवसर भी दिया जाना चाहिए।

156. यह कहना पर्याप्त है कि यद्यपि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के उपरोक्त सिद्धांतों पर थोड़ा-सा भी संदेह नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले के तथ्यों में यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य ने उपरोक्त सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के खिलाफ अपना अभ्यावेदन दायर करने का उचित अवसर दिया गया है। इसके अलावा, पहली पुनरीक्षण समिति, अभ्यावेदन

समिति के साथ-साथ दूसरी पुनरीक्षण समिति ने याचिकाकर्ता के सम्पूर्ण सेवा रिकॉर्ड की जांच है। वास्तव में, जब प्रत्यर्थी द्वारा 1 जून, 2018 के अभ्यावेदन की गहराई से जांच की गई, तो उसने याचिकाकर्ता के मामले को नए सिरे से विचार के लिए पुनरीक्षण समिति को वापस भेज दिया और उसके बाद ही, दूसरी पुनरीक्षण समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिकाकर्ता की सेवा की अब आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त निर्णय भी वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा।

157. अतः उपरोक्त से यह पुर्णतः स्पष्ट है कि श्री घोष द्वारा जिन उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होंगे और इसलिए याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करेंगे।

158. ऐसा कहने के बाद, ऊपर की गई हमारी विवेचन को देखते हुए, हम वर्तमान याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं। अधिकरण के आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। रिट याचिका खारिज की जाती है। कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है।

<u>सि.वि.आ. 25969/2021</u>

निष्फल होने के कारण खारिज की जाती है।

वी. कामेश्वर राव, न्या.

अनूप कुमार मेंदिरत्ता, न्या.

18 जनवरी, 2024/*ए.के. वाई*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*